04 - प्राकृतिक संपदा को बचाना मतलब मानवता बचाना

05 - पर्यावरण की सुरक्षा करना हर हाल में जरूरी

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 27 जुलाई, 2026

06 - बरसात के मौसम में लीक से अलीक तक

07 - औद्योगिक कार्यप्रणाली और रोजगार के अवसरों से हुई रूबरू

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 325, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या जेन ज़ी ने सरकार के प्रति डर को खत्म कर दिया है?

प्रवीण

बीते कुछ वर्षों में साउथ एशिया में एक शब्द जिसकी गूंज काफ़ी सुनने को मिली है, तो वह हैः जेन ज़ी। जेन ज़ी वह पीढ़ी है, जिसने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता को बदलकर रख दिया। पिछले दो महीनों में जेन ज़ी भारत की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बनकर उभरी। नीट-यूजी का पेपर लीक होने के बाद भारत के जेन ज़ी ने एक आंदोलन की शुरुआत की।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुवाई में जेन ज़ी का आंदोलन शुरू हुआ। चूंकि इस आंदोलन की अगुवाई सीजेपी कर रही थी, इसलिए शुरुआत में विपक्षी दलों ने भी इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन बीते एक हफ़्ते में जेन ज़ी का यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि तमाम विपक्षी दलों को इसका साथ देना पड़ा। यह इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया।

बीते 12 वर्षों में मोदी सरकार एक बात को अपनी मजबूती की तरह दिखाती थी। लेकिन जेन ज़ी ने मोदी सरकार की इस यूएसपी को ब्रेक कर दिया है। जेन ज़ी के आंदोलन की मुख्य मांगों को मोदी सरकार ने स्वीकार किया। कैबिनेट से केंद्रीय मंत्री के इस इस्तीफ़े के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को ख़त्म कर दिया। लेकिन जिस कामयाबी के साथ जेन ज़ी का यह आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद यह सवाल निकलना लाज़िमी है कि यहां से भारत की राजनीति किस ओर रुख करेगी और उसमें जेन ज़ी की क्या भूमिका होगी।

आंदोलन पर नज़र रखने वाले और उसे कवर करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेन ज़ी के इस आंदोलन की छाप आने वाले कई वर्षों तक भारत की राजनीति पर देखने को मिलेगी। 20 जुलाई के बाद से ही जंतर-मंतर पर जो कुछ देखने को मिला, वह कई मायनों में भारत में पहले हुए आंदोलनों से अलग था। जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शन में बेबाक नारे, पोस्टर, गाने, डांस, धूप या बारिश में डटे रहने का हौसला तो था ही। साथ ही, डिलीवरी ऐप्स का जिस तरह इस्तेमाल देखने को मिला, वह अपने आप में ऐसी जगह पर संसाधन जुटाने का नया तरीका दे गया, जहां टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना डटे रहने को बेहद मुश्किल बनाता है।

आंदोलन के पहले दिन से इसकी गवाह रहीं स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा कहती हैं, 'जो आज हुआ है, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अहम क्षण है, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़रूरी कोर्स करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र और उसमें लोगों का विश्वास भी क़ायम हुआ है।'

भारत के सोशल स्ट्रक्चर से अलग, इस आंदोलन ने शिक्षा के मुद्दे पर जेन ज़ी को एकजुट किया। इस आंदोलन में जिसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, वे थे स्कूल-कॉलेज के छात्र और अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लड़के-लड़कियां। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक विजय त्रिवेदी कहते हैं, 'जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल बॉक्सेस हैं, जाति और धर्म से अलग होकर यह आंदोलन था और बिना किसी राजनीतिक दल के मोटे तौर पर सहयोग के, यह अपने आप खड़ा हो गया। बिना किसी के कॉल किए, वे लोग अपने आप आकर खड़े हो गए। और सब राजनीतिक दलों को जगा भी दिया और दबाव में भी ला दिया। सत्तापक्ष तो, ज़ाहिर है, दबाव में आ ही गया कि मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया और विपक्ष को भी दबाव में ला दिया कि सभी लोग एकजुट होकर क़रीब-क़रीब उनके साथ आ गए।'

वहीं वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया गया है। जेन ज़ी का आंदोलन ऐसा सवाल था, जो सरकार के लिए 'आउट ऑफ सिलेबस' का सवाल बनकर आ गया। उसे हल्के में लिया गया। लेकिन यह सरकार पर उल्टा पड़ गया।

इंस्टाग्राम वह प्लेटफॉर्म है, जिसे जेन ज़ी का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। इस आंदोलन का भी सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला। बीते एक हफ़्ते में इंस्टाग्राम पर जंतर-मंतर से जुड़ी रील्स की बाढ़ आ गई थी। इंस्टाग्राम चलाने वाले अधिकतर यूज़र्स आंदोलन से जुड़ी रील्स के बारे में ही बातें करने लगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले गुरुवार और फिर शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट कीं। इस आंदोलन से राजनीतिक दलों को क्या सबक मिलता है, इस बारे में बात करते हुए स्मिता शर्मा कहती हैं, 'बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है, जिसने 2013 से, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही, अपनी कैंपेन के नैरेटिव बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात स्थापित हो गई कि आप सोशल मीडिया पर दिनभर अगर एकतरफ़ा नैरेटिव देंगे, तो एक वक़्त ऐसा आता है, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है और वही हुआ।' आदेश रावल कहते हैं, 'इस आंदोलन में छात्रों ने मोदी सरकार को इंस्टाग्राम पर हरा दिया। यानी सरकार छात्रों से डरी। हर रोज़ की जो फ़ीड थी, उससे भी वह घबराई। जेन ज़ी ने सरकार को झुकाकर दिखाया।' स्मिता शर्मा मानती हैं कि विपक्ष के लिए भी मैसेज है कि लड़ाई सोशल मीडिया से आगे सड़क पर लड़ी जाती है।

यह सवाल भी है कि अब जेन ज़ी की भारत के राजनीतिक भविष्य में क्या भूमिका होगी?

विजय त्रिवेदी कहते हैं, 'अभी तक, अगर हम पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखें, तो उसमें दो-तीन तरह के वोट बैंक रहे हैं। एक वोट बैंक पिछड़ों और ग़रीबों का था। राजनीतिक दल उन्हें चीज़ें दे रहे थे, लैपटॉप दे रहे थे। फिर दूसरा दौर आया, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक दलों ने वोट बैंक बनाया। अब इस आंदोलन ने यह फ़ोकस तय कर दिया है कि अगले चुनावों का वोट बैंक युवा होंगे। आदेश रावल जेन ज़ी के आंदोलन को भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार के इस दौर में, जहां इतना डर था, वहीं जेन ज़ी के इन युवाओं ने पिछले पांच दिन में मोदी सरकार का इक़बाल ख़त्म कर दिया। कैसे-कैसे स्लोगन्स, कैसे-कैसे नारे और मीम्स चलाए गए, दिखाए गए और बताए गए। वो भी पुलिस के सामने. तो मुझे लगता है कि यह एक नई शुरुआत है।'

स्मिता शर्मा कहती हैं, 'इस आंदोलन का इलेक्टोरल आउटकम सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद बस यही की जा सकती है कि कम से कम जो युवा पॉलिटिकली जागरूक नज़र आए हैं। नीतियों को बदलना होगा, तो राजनीति पर नज़र रखनी होगी।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत

पीएम ने आईएनएस महेंद्रगिरि और पिनाका रॉकेट प्रणाली का किया जिक्र

कहा-इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों-इंजीनियरों की सामूहिक मेहनत है

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश अपने सशस्त्र बलों के साहस के साथ-साथ अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने आईएनएस महेंद्रगिरी, पिनाका रॉकेट प्रणाली और कुशा मिसाइल का जिक्र कर भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी के शामिल होने को स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में भारत की प्रगति के उदाहरण के रूप में बताया। पीएम मोदी ने आईएनएस महेंद्रगिरी की खूबियां बताते हुए कहा कि यह आधुनिक युद्धपोत भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने पिनाका का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (एलआरजीआर-120) का भी जिक्र किया, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक उन्नत सटीक निर्देशित तोपखाना रॉकेट प्रणाली है। इस प्रणाली की प्रमाणित मारक क्षमता 60 किमी से 120 किमी तक है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सामूहिक मेहनत है। प्रधानमंत्री ने कुशा मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण पर भी प्रकाश डाला और इसे भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक और मील का पत्थर बताया।

कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हर भारतीय को गर्व से भर देता है और सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा,हमारे जीवन में कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जिनके लिए हमें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती।

आज, 26 जुलाई, ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। यह दिन हमें गर्व से भर देता है और हमारे बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस की याद दिलाता है। कारगिल की विशाल चोटियां, भीषण मौसम, शत्रु द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां, हमारे सैनिकों ने हर परिस्थिति का सामना किया, फिर भी उनका मनोबल हर चुनौती से कहीं अधिक था। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।

सुप्रभात

चलते थे नंगे पांव,
अलगें ही ठीक थीं।
सड़कें बिछीं तो गांव की
क्यारी निगल गईं।।
पुरखों के खेत कौड़ियों में
बिक गए, वो भी।
आधी 'बीमारी',
आधी 'उधारी' निगल गई।।
भाई की ऐसे भाई से,
छूटी हथेलियाँ।
भैयारे पे भारी 'गोतियारी'
निगल गई।।
बचपन निगल गया
मेरा दिन चार का यौवन।
मासूमियत को कोई
'खुदारी' निगल गई।।
शौक़त दिखा रहे थे
वो हमको गुरूर से,
आतिथ्य को दौलत की
खुमारी निगल गई।
अपनत्व खा गए सभी
ईर्ष्या के पुलिंदे,
रिश्तों को शिकायत की
पिटारी निगल गई।
अब रूठे की खुशामदें
की भी नहीं जातीं।
सब मान-मुनव्वल
मनुहारी निगल गई।।
पलकों पे पल रहे थे
ख्वाब एक उम्र से।
कन्धों की जिम्मेदारियाँ
सारी निगल गईं।।

- पियूष प्रणव सुमित

तमिलनाडु में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट

तीन लोगों की मौत,अन्नामलाई ने की निष्पक्ष जांच की मांग

विरुधुनगर (एजेंसी)। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास रविवार सुबह एक पटाखा बनाने वाली अवैध फैक्टरी में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार, शिवकाशी के निकट एक टिन शेड में कथित तौर पर अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम चल रहा था।

ओरछा में रामराजा के दर्शन के बाद निवाड़ी पहुंचे सीएम

कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का लोकार्पण किया

निवाड़ी (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का निवाड़ी दौरा जिले के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। ओरछा में भगवान रामराजा सरकार के दर्शन और रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री निवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया एवं ओरछा के जहांगीर महल का भ्रमण किया। बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आन-बान-शान के लिए इस वीर भूमि ने हमेशा डटकर मुकाबला किया है और अब सरकार यहाँ विकास की नई इबारत लिख रही है।

कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का लोकार्पण- मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर लगभग रू. 2,563 करोड़ की लागत से बने नवीन संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट भवन और करीब रू. 1,998 करोड़ की लागत वाले 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 110 करोड़ की लागत वाले 44 अन्य विकास कार्यों की सौगात भी जिले को मिली। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को ट्राइसाइकिल और छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। मंच पर पारंपरिक रूप से कन्या पूजन और दीप प्रज्ज्वलन भी किया गया।

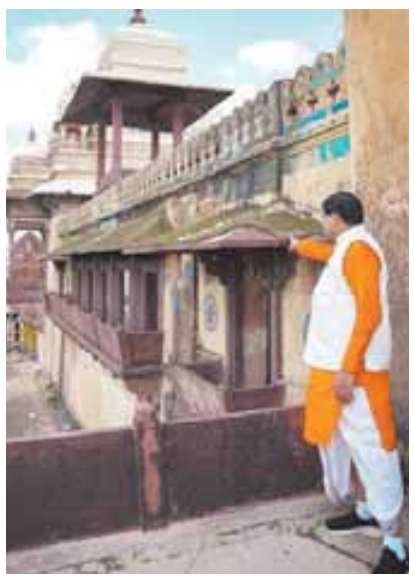

साथ में मौजूद रहे स्थानीय नेता- मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, जिलाध्यक्ष राजेश पटेरिया निवाड़ी विधायक अनिल जैन सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

केन-बेतवा परियोजना से बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि रू. 1 लाख करोड़ की इस योजना से निवाड़ी के 158 गांवों को पानी मिलेगा, जिससे क्षेत्र से पलायन रुकेगा। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। यह दौरा निवाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक बड़ा संदेश दे गया।

निवाड़ी को मिलीं कई नई घोषणाएं

क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन की मांगों पर त्वरित कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सिमरा खास में सांदीपनि विद्यालय खोलने, निवाड़ी और पृथ्वीपुर में गीता भवन निर्माण, जनौली-चंदावनी मार्ग पर पुल, निवाड़ी में आधुनिक बस स्टैंड और तरीचरकलां में गौशाला निर्माण की घोषणा की। इससे पहले विधायक अनिल जैन ने काव्यात्मक अंदाज में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए निवाड़ी के विकास को नई दिशा देने के लिए आभार जताया।

फोर्स का इस्तेमाल तय मानकों के मुताबिक नहीं हुआ

सीजेपी के संसद चलो मार्च पर आ गई आरएएफ की रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज और तीन प्रदर्शनकारियों के पेलेट गन से घायल होने के मामले में सुरक्षा एजेंसियों के भीतर से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की महानिरीक्षक (डीजी) सीमा धुंधिया ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारियों पर किया गया बल प्रयोग निर्धारित मानकों और आरएएफ की ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं था। 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात कंपनी कमांडरों और कमांडेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक

उच्चस्तरीय बैठक में डीजी सीमा धुंधिया ने माना कि उस दिन फोर्स ग्रेडिएंट यानी परिस्थिति के हिसाब से कदम दर कदम बल प्रयोग करने में गंभीर चूक हुई है। आंतरिक समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और भविष्य के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। डीजी सीमा धुंधिया ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन जवानों का तबादला हाल ही में जम्मू-कश्मीर या दूसरे स्पेशल ऑपरेशन्स (आतंकवाद रोधी/उग्रवाद रोधी) क्षेत्रों से हुआ है।

मीराबाई चानू की स्वर्णिम हैट्रिक

ऐतिहासिक प्रदर्शन,भारोत्तोलन में गोल्ड जीतकर भारत को दिलाया गौरव

नईदिल्ली (एजेंसी)। मीराबाई चानू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध की, जो उनके करियर का तीसरा सीडब्ल्यूजी गोल्ड है। स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में नए रिकॉर्ड स्थापित करना उनके निरंतर उच्च प्रदर्शन और शारीरिक क्षमता के विश्लेषण को दर्शाता है। ग्लासगो में रविवार को महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर मणिपुर की साइखोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया।

पेपर लीक के खिलाफ आज संसद में आ सकता है बिल

जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे,10 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है।

स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट

बिल में दो नई धाराएं 12ए और 12बी जोड़ी गई हैं। इसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसआईटी को केंद्र सरकार द्वारा मामला सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 27 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

उज्जैन के वरिष्ठ नागरिक द्वारा रेलवे की पार्किंग बचाने के लिए पहल

प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी

उज्जैन के एक वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री कृष्णकुमार अटल ने इंदौर गेट स्थित उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर प्रस्तावित केबल कार (रोपवे) स्टेशन के निर्माण के स्थान पर पुनर्विचार करने और उस स्थान को रेलवे पार्किंग के लिए सुरक्षित रखने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय रेल मंत्री को एक पाती लिखी है।

पिछले सप्ताह लिखी इस चिट्ठी में श्री के.के अटल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री को निवेदन किया है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन के इंदौर गेट स्थित प्रवेश द्वार के बाहर पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार इस स्थान पर महाकाल कॉरिडोर हेतु केबल कार स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं इस योजना के उद्देश्य का पूर्ण सम्मान करता हूँ तथा महाकाल नगरी में आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विकास का स्वागत करता हूँ। तथापि, मेरा विनम्र निवेदन है कि केबल कार स्टेशन के लिए इस स्थान का चयन पुनर्विचार योग्य है।

उज्जैन के इस वरिष्ठ नागरिक ने इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित बताएं है –

1. रेलवे स्टेशन की प्राथमिक आवश्यकता पार्किंग है। उज्जैन आने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर उपलब्ध यह खुला स्थान पार्किंग एवं यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. अधिकांश यात्री सीधे महाकाल मंदिर नहीं जाते। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अधिकांश श्रद्धालु पहले अपने होटल, धर्मशाला अथवा निवास स्थान पर जाकर सामान रखते हैं, स्नान-विश्राम करते हैं और उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। इसलिए रेलवे स्टेशन से सीधे केबल कार की उपयोगिता सीमित रहेगी।
3. रेलवे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी। यदि केबल कार स्टेशन रेलवे स्टेशन के बाहर बनाया जाता है, तो ऐसे लोग भी वहाँ पहुँचेंगे, जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं होगा। इससे रेलवे स्टेशन परिसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
4. यातायात एवं पार्किंग की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। रेलवे यात्रियों, टैक्सी, ऑटो, निजी वाहनों तथा केबल कार उपयोगकर्ताओं की संयुक्त आवाजाही से ट्रैफिक जाम एवं अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।
5. भविष्य की दृष्टि से यह स्थान अत्यंत मूल्यवान है। रेलवे स्टेशन के आसपास खुली भूमि भविष्य में पुनः उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः इस स्थान का उपयोग केवल रेलवे से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सुरक्षित रखा जाना अधिक दूरदर्शी निर्णय होगा।

श्री अटल ने इस संबंध में अपने सुझाव देते हुए लिखा है कि केबल कार परियोजना निश्चित रूप से जनहित की योजना है। परंतु उसका स्टेशन किसी ऐसे स्थान पर विकसित किया जाए, जहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। यातायात का दबाव कम हो तथा रेलवे स्टेशन की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं हो। रेलवे स्टेशन के बाहर उपलब्ध संपूर्ण खुला क्षेत्र रेलवे पार्किंग, ड्रॉप-ऑफ जोन, बस-टैक्सी प्रबंधन तथा भविष्य के यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए आरक्षित रखा जाए। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री और रेल मंत्री भारत सरकार इस विषय पर तकनीकी एवं यातायात विशेषज्ञों से पुनः अध्ययन कराकर जनहित में उचित निर्णय लेंगे।

वरिष्ठ नागरिक श्री के.के अटल ने रेलवे पार्किंग को सुरक्षित रखने के संबंध में जो पहल की है, वह सराहनीय है। उन्होंने स्थान परिवर्तन के जो प्रमुख कारण बताएं हैं वे भी अत्यन्त गंभीर और विचारणीय है। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री और रेल मंत्री उनके सुझाव पर गंभीरतापूर्वक सोच-विचार कर जनहित में निर्णय लेंगे।

संक्षिप्त समाचार

सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के बहाने सपा पर कसा तंज

- कहा-केसरिया कपड़े से तो सपा को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो

इटावा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इटावा में रविवार को आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने कहा- पहले समाजवादी पार्टी कहती थी, कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख

नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी है। सभा में उपस्थित जनता को सावधान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो लोग आएंगे, फिर से कालरात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। ये लोग पहचान का संकट खड़ा करेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे।

जो व्यक्ति 12 बजे उठेगा, उसका तो भगवान ही मालिक है

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। उन्होंने कहा- जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठेगा, उसका तो भगवान ही मालिक है, यही यूपी की दुर्गति का कारण था। आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं, बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है।

स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया

- राहुल गांधी का सरकार से सवाल, शाह को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें राहुल ने दो सवाल पूछे हैं। पहला- प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया। दूसरा- सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, वे पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स उनकी तैनाती किसने की। राहुल ने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स से बात करने के बजाय सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कइयों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया।

19 साल के छात्र साहिल लोचब की एक आंख चली गई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका जेपी नड्डा से मिले और उनके सामने देश में शिक्षा सुधार के लिए 5 मांगें रखीं। इनमें पेपर लीक मामलों में 10 साल की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त करने, नया नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाने और नियुक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की था। रहुल ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं।

शिवपुरी में टीआई ने 50 के स्टाम्प पर लिखा

आजीवन न नशा लूंगा और न गाली दूंगा, नियम तोड़ा तो छोड़ दूंगा नौकरी

शिवपुरी (नप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से पुलिस महकमे के भीतर से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायी खबर सामने आई है। यहां के अजाक थाने के प्रभारी आचार्य डॉ. रणजीत सिंह रघुवंशी ने समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। उन्होंने पूरी तरह स्वेच्छा से आजीवन नशामुक्त और गाली-मुक्त जीवन जीने का कड़ा संकल्प लिया है।

डॉ. रघुवंशी ने 23 जुलाई 2026 को 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर एक ऐतिहासिक शपथपत्र जारी किया है। इस हलफनामे में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि वे चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, मांस, मछली और अंडे समेत किसी भी प्रकार के नशे या व्यसन का सेवन नहीं करते हैं और अपनी अंतिम सांस तक ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्रण लिया है

कि वे जिंदगी में कभी किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्द या गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

नौकरी छोड़ने तक की रख दी शर्त- इस शपथपत्र की सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें खुद टीआई ने अपने ऊपर कड़ा अनुशासन लागू किया है। हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि यदि भविष्य में उनकी किसी भी घोषणा का उल्लंघन साबित होता है, तो पुलिस विभाग यदि उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी करता है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

समाज और पुलिस विभाग के लिए बड़ा संदेश- डॉ. रणजीत सिंह रघुवंशी का यह कदम न केवल पुलिस विभाग के भीतर बल्कि आम समाज के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन गया है। उनका मानना है कि एक पुलिस अधिकारी का आचरण हमेशा समाज के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। जब तक अधिकारी और कर्मचारी खुद संयमित और नशामुक्त जीवन नहीं जिएंगे, तब तक एक स्वस्थ और आदर्श समाज का निर्माण संभव नहीं है। उनकी इस पहल ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो खाकी वर्दी के भीतर रहकर भी उच्च नैतिक मूल्यों की मिसाल कायम की जा सकती है।

संकल्प : एक नजर में

- **अधिकारी का नाम-** आचार्य डॉ. रणजीत सिंह रघुवंशी (थाना प्रभारी, अजाक थाना, शिवपुरी)
- **शपथ की तारीख-** 23 जुलाई 2026
- **माध्यम-** 50 रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर
- **मुख्य संकल्प-** आजीवन नशामुक्त, मांसाहार मुक्त और पूरी तरह गाली-मुक्त जीवन
- **बड़ी शर्त-** नियम टूटने पर पुलिस विभाग द्वारा सेवा से हटाने पर भी पूर्ण सहमति

अंग्रेजी के 'ए' ने खोला राज, जिसे एक्सीडेंट समझा

वो निकली खौफनाक हत्या की साजिश, एक के चक्कर में ली 5 बेकसूरों की जान

नरसिंहपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शुरुआत में जिसे पुलिस एक सामान्य और दर्दनाक सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही थी, वह असल में एक सुनियोजित मर्डर प्लॉट निकला। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों (टेक्निकल एविडेंस) ने इस पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी हैं।

नरसिंहपुर के एसपी ऋषिकेश मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह साजिश सिर्फ एक शख्स को रास्ते से हटाने के लिए रची गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि उस टारगेट के पास खड़े पांच अन्य लोगों की भी इस खूनी खेल में जान चली गई। जो घटना पहले महज एक सड़क हादसा लग रही थी, वह पुलिस की कड़ी जांच के बाद एक सोची-समझी हत्या की साजिश साबित हुई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी राजेंद्र और आनंद पटेल के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोप है कि इस दुश्मनी को पूरा करने के लिए राजेंद्र पर लगातार नजर रखी जा रही थी।

भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स

रक्षामंत्री बोले-भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा तो पाक घुसपैठ के

नईदिल्ली (एजेंसी)। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। साफ है कि हमारे रास्ते अलग-अलग हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़े खड़े करता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर

भारत की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी भी, तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। कारगिल वॉर मेमोरियल में पूरा भारत दिखाई देता है। यहां शहीदों में हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, तमिलनाडु समेत देश के हर हिस्से के जवानों के नाम दर्ज हैं। शहीदों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने वाले सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जो लोग देश को बांटने का सपना देखते हैं, उन्हें इस स्मारक की दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार ही भारत को बांटने की उनकी सोच का सबसे बड़ा जवाब है।

जल्द खत्म होगा सिलीगुड़ी का वर्षों का इंतजार

- सीएम शुभेंदु करेंगे वर्दवान रोड फ्लाईओवर का शुभारंभ

सिलीगुड़ी (एजेंसी)। शहर वासियों के सब्र का बांध और जाम का दर्द खत्म होने जा रहा है। महात्मा गांधी स्कायर (एयरव्यू मोड़) से वर्दवान रोड को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार यानी 27 जुलाई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 1.124 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के पहले रविवार को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सैयद वकार रजा ने सुरक्षा और ट्रैफिक ट्रायल की बारीकियों का निरीक्षण किया।

2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सिद्धारमैया

किया ऐलान, बोले-आज के समय में राजनीति भ्रष्ट हो गई है

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने कहा है कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि, वह राजनीति में सक्रिय रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने शनिवार को मंड्या जिले के केआर पेट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा- राजनीति अब पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और ईमानदार राजनीति के लिए जगह नहीं बची है। सिद्धारमैया ने कहा- मैं अब 79 साल का हो चुका हूं। हमारी सरकार का कार्यकाल अभी करीब डेढ़ साल बाकी है। तब तक मेरी उम्र 81-82 साल हो जाएगी। मेरी सेहत पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अब पहले जैसे उत्साह के साथ काम करना संभव नहीं है।

चुनाव लड़ना हो तो नेताओं को ही लोगों को पैसे देने पड़ते हैं

सिद्धारमैया ने कहा- अब ऐसा समय आ गया है कि चुनाव लड़ना हो तो नेताओं को ही लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। 2028 तक मैं 82 साल का हो जाऊंगा। उस समय मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे हो जाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा- मैंने 1978 में तालुक बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। मैंने हार और जीत, दोनों देखी हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कभी अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं किया और न ही अपनी अंतरात्मा से समझौता किया।

ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रम्प

- अमरीकी सेना को कार्रवाई रोकने का दे दिया आदेश

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रम्प ने सेना को नए बड़े हमले रोकने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान और बढ़ाया गया तो मिडिल-ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी कि बड़े अभियान से मिडिल-ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था। एक्सियोस के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमले रोकने का फैसला अस्थायी है या लंबे समय तक लागू रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार रहेगी।

प्रधान के एग्जिट के बाद प्रल्हाद जोशी की एंट्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर संभाल लिया पदभार

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक एक दिन बाद रविवार को प्रल्हाद जोशी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। धारवाड़ से पांच बार के सांसद प्रल्हाद जोशी इससे पहले कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में, प्रल्हाद जोशी ने कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मंत्री पदों का कार्यभार संभाला है। 2019 से 2024 के बीच उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्य किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री के रूप में, प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों सहित कई प्रमुख सरकारी पहलों की देखरेख की है।

शिक्षा मंत्री के सामने कई चुनौतियां

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही वे अपने मौजूदा मंत्रालयों का काम भी संभालते रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रल्हाद जोशी के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और छात्रों का भरोसा मजबूत करना प्रमुख हैं। गौरतलब है कि शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर किया गया। इसके बाद प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया।

मन की बात जन-जीवन को नई दिशा देने वाला अभियान : राज्यपाल

प्रधानमंत्री की मन की बात राज्यपाल ने सुनी छात्राओं के साथ

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'मन की बात' कार्यक्रम ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा का सतत प्रवाह है। यह जन-जीवन को नई दिशा देने वाला जन अभियान है। प्रधानमंत्री की प्रत्येक 'मन की बात' गागर में सागर के समान होती है। कम समय में गहन विचार और उपयोगी संदेश देती हैं। यह कार्यक्रम ज्ञान का ऐसा भंडार है, जिसमें जीवन को सरल, सफल और सार्थक बनाने वाले अनेक प्रेरक संदेश समाहित रहते हैं। हमारे विचारों को समृद्ध और दृष्टि को व्यापक बनाते हैं। अनेक विषयों की उपयोगी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त होती है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस कार्यक्रम में

देश के हर क्षेत्र से ऐसे प्रेरक प्रसंग बताते हैं, जो सामान्य लोगों के असाधारण प्रयासों का परिचय कराते हैं। यह संदेश देते हैं कि जागरूक और उत्तरदायी नागरिकों के प्रयासों से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से कहा कि आप देश का वर्तमान ही नहीं, बल्कि भविष्य भी हैं। आप सभी इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनने की आदत विकसित करें। इस प्रेरक कार्यक्रम के प्रत्येक एपिसोड को दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। राज्यपाल श्री पटेल रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के पूर्व कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय की छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल के साथ छात्राओं, शिक्षकगण, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संस्थान के सभागार में मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया।

छोटे-बड़े व्यक्तियों का करें सम्मान, उनसे सीखते रहें

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से छात्राएं समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प लें। समाज के वंचित, गरीब और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता के संस्कार सीखें। जीवन भर निरंतर सीखने का भाव रखें। हर छोटे-बड़े व्यक्ति का सम्मान करें। उनकी मौलिकता और विशेषताओं से सीखते रहें। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से भी कहा कि विद्यार्थियों को अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार और समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व का महत्व बतायें। उनमें हमेशा देश का मान बढ़ाने की भावना विकसित करें। विकसित भारत के नव-निर्माण में सहभागिता के लिये उन्हें प्रेरित करें।

प्रदर्शनी का अवलोकन कर की सराहना

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय की छात्राओं दवारा निर्मित विज्ञान, इतिहास, कला और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। छात्राओं से प्रदर्शनी के विषयों की जानकारी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने छात्राओं के प्रदर्शनी मॉडल, प्रस्तुतिकरण और नवाचार प्रयासों की सराहना की। छात्राओं के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्थान के समुचित प्रबंधन के लिए विद्यालय को बधाई दी। विधायक श्री भगवान दास सबनानी ने मन की बात कार्यक्रम को हर व्यक्ति-हर वर्ग के लिये उपयोगी और प्रेरणा का स्रोत बताया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल का कलेक्टर भोपाल श्री प्रियंक मिश्र ने पौधा भेंट कर स्वागत किया। लोक शिक्षण विभाग के संचालक श्री डी. एस. कुशवाहा ने छात्राओं द्वारा निर्मित गोंडी पैंटिंग को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर अभिनंदन किया। प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना ने विद्यालय के शैक्षणिक नवाचारों और उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में पार्षद श्रीमती आरती अनेजा, विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित थीं।

उत्कृष्ट कार्यों को मिलती है राष्ट्रीय पहचान

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को नियमित सुनने से नया उत्साह, नया विश्वास और नए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा का संचार होता है। जीवन की अनेक कठिनाइयों के समाधान को सकारात्मक सोच, जन-भागीदारी और सतत प्रयासों से संभव बनाने की सीख मिलती है। इस कार्यक्रम में देशभर के उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान होता है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। नवाचार, परिश्रम और सफलता की प्रेरक कहानियाँ पूरे देश के सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका, विकास, जन-कल्याण और समाज हित के अनेक सफल प्रयास इस कार्यक्रम की विशेष पहचान बन चुके हैं। देश के विभिन्न भागों में हो रहे अच्छे कार्य बताते हैं कि हर छोटा-बड़ा और बुजुर्ग अपने-अपने स्तर पर परिवर्तन का सहभागी बन सकता है।

बच्चों से घर में लोकभाषा में बात करें : डॉ. किशन तिवारी

भोपाल। मध्यप्रदेश लेखक संघ की प्रादेशिक लोकभाषा पद्य/गद्य गोष्ठी रविवार को दुष्यंत संग्रहालय, शिवाजी नगर, भोपाल में वरिष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि, वरिष्ठ गज़लकार डॉ. किशन तिवारी ने कहा कि बच्चों से घर में लोकभाषा में बात करनी चाहिए एवं बुंदेली में सुनाया, 'हो गई भौत ही जीभ चटोरी, बात सुनत नहीं मोरी' अध्यक्षीय उद्बोधन में संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष राजेंद्र गट्टानी ने संघ की नवीन गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. प्रार्थना पंडित की सरस्वती वन्दना से हुई। पहले कवि के रूप में तराना से पधारे, विक्रम विवेक ने मालवी में सुनाया, 'बईरा ने एस्तर आखी रात माथो फोड़ियो, जदे कई जई ने पन्ना बा ने दारु छोड़ियों'। खरगोन से पधारे छोगालाल कुमरावत 'सुजस',ने निमाड़ी ग़ज़ल सुनाई, 'काइ खाइनऽ फाकोज दादा? चस्मा सी खूब ताकोज दादा।' भोपाल के राजेश तिवारी ने बुंदेली में सुनाया 'हड्डी जमा देय वो जाड़ो, भुनसारे आंगन में ठाड़ो, जाड़ो पर रओ भैया भारी, घर में ही है खैर तुम्हारी' और खूब वाहवाही लूटी। धामनोद से आये निर्मल शर्मा ने निमाड़ी में सुनाया, 'हम दई रहिया ज कलेजा को टुकड़ों, राखजो एक संभाली न, या छे हमारा दो कुल की लाज, राखजो एक संभाली न'। ग्वालियर से पधारी कवयित्री आशा पाण्डेय ने बुंदेली रचना में बेटियों की बिदाई का दृश्य दिखाकर माहौल मार्मिक कर दिया, 'बिन्नू बिन घर हो गओ खाली, परसो लग रओ बिना नोन को, बिन बिलिअन की थाली'। भोपाल के सत्यदेव सोनी सत्य ने बघेली में सुनाया, 'वेदहिं नारि बखान करैं अरु स्तुति वेद पुराणहिं गावैं, नारि रचैं रचना, जगजीवन सृष्टि अधारहिं नारि कहावैं। उज्जैन की संगीता तलेरा ने मालवी में जाड़े पर रचना सुना के खूब गुदगुदाया, 'कतरी ठंड पड़वा लग गी, उज्जैन में भी कुल्फू-मनाली की हवा चलवा लग गी।' भिण्ड से पधारे सुनील त्रिपाठी निराला ने बुन्देली में चौकड़िया छंद सुनाया, उनको बाप बड़ौ ना भैया, सबसे बड़ौ रुपैया। बिना घूस के वे नइं धर रए, अपई कहूं चिरैया'। दतिया से पधारे विनोद मिश्र सुरमणि ने बुंदेली में सुनाया, 'बरसा उने करें बेचैन, जिनके सूखे नैन, दादुर मोर पपीहा बिजुरी लगे हैं गारी देंन'। मंचासीन अतिथियों में मध्यप्रदेश लेखक संघ के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ गीतकार ऋषि श्रृंगारी ने सुनाया, 'हम जानत तुम इत गरजोगे उत बरसोगे रे, ओ बदरा कित बरसोगे रे'। विशिष्ट अतिथि एवं मध्यप्रदेश लेखक संघ के संरक्षक डॉ. राम वल्लभ आचार्य ने सुनाया, 'अब तो गाँव शहर में आ रओ, मोड़ा फ़िल्मी गानो गा रओ'। मुरेना से पधारे सारस्वत अतिथि कैलाश गुप्ता 'सुमन' ने एक बच्ची की व्यथा यूँ सुनाई, 'ब्याहो जिन करियो ओ महतारी, अबे उमर है बाली' एवं सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम संचालन संघ के प्रांतीय मंत्री मनीष बादल एवं सह मंत्री डॉ. प्रार्थना पंडित ने किया। कोषाध्यक्ष सुनील चतुर्वेदी ने अपने पिता की बुंदेली रचना के साथ धन्यवाद ज्ञापन किया।

शिरीष साठे अध्यक्ष, यश बुचके सचिव निर्वाचित

भोपाल। महाराष्ट्र समाज भोपाल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। गत सप्ताह हुए चुनाव में निर्वाचित सदस्यों की आज बैठक चुनाव अधिकारी अरविंद खोडके की अध्यक्षता में महाराष्ट्र समाज में सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से शिरीष साठे, अध्यक्ष, विनोद खंगन उपाध्यक्ष, यश बुचके सचिव, रामचंद्र घाणेकर कोषाध्यक्ष, सतीश अपशंकर, सोनाली पुणतांबेकर को सहसचिव चुना गया व विलास बुचके, विद्या चौधरी, विजय अपशंकर, विजय रानडे, समीर दीक्षित, मदन टंगसाले, विजय मराठे, भरत साठे, श्रीपाद कुंडले कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। यह जानकारी समाज के अध्यक्ष विलास बुचके ने दी।

मुख्यमंत्री ने स्क्वैश चैंपियन बेटी अनाहत सिंह को दी बधाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप-2026 में गर्ल्स सिंगल्स जीतने वाली प्रतिभाशाली बेटी अनाहत सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि बेटी अनाहत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह भारत की बढ़ती खेल उत्कृष्टता का सशक्त प्रमाण भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी अनाहत सिंह को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगलकामनाएं दीं।

निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए दतिया विधानसभा क्षेत्र से बदले गए सात पुलिस अधिकारी

भोपाल (नप्र)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 के उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सात निरीक्षक एवं उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों को दतिया विधानसभा क्षेत्र से अविलंब अन्यत्र पदस्थापित करने के निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों के परिपालन में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा उक्त सात पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय भोपाल में करते हुए उनके स्थान पर अन्य पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना कर दी गई है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अजाक थाना दतिया में पदस्थ निरीक्षक श्री केहरी परिहार के स्थान पर पुलिस मुख्यालय से निरीक्षक श्री मेलीराम उइके की पदस्थापना की गई है। इसी प्रकार थाना सिविल लाइन दतिया में पदस्थ उप निरीक्षक श्री अमित ओसारे के स्थान पर उप निरीक्षक अशोक नगर श्री भोजराम भगत, थाना बड़ौनी में पदस्थ उप निरीक्षक श्री नीरज कुमार के स्थान पर उप निरीक्षक भिंड श्री कौशलेन्द्र सिंह गुर्जर, थाना जिगना में पदस्थ उप निरीक्षक सुश्री रचना माहौर के स्थान पर उप निरीक्षक ग्वालियर श्री राजीव बिरथरे, थाना गोराघाट में पदस्थ उप निरीक्षक सुश्री अर्चना पाल के स्थान पर उप निरीक्षक ग्वालियर श्री बलराम मांझी, थाना धीरपुरा में पदस्थ उप निरीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह जाट के स्थान पर उप निरीक्षक अशोक नगर श्री भुवनेश शर्मा तथा थाना बड़ौनी में पदस्थ उप निरीक्षक श्री हरिओम शर्मा के स्थान पर उप निरीक्षक ग्वालियर श्री हरिकेश बघेल की पदस्थापना की गई है। सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैग रिपोर्ट में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है एमपी में मानसिक रोगियों का आंकड़ा

100 में से 14 लोग मानसिक बीमारी के शिकार

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश की सरकारी मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक राज्य में उपकरणों की 100 प्रतिशत तक कमी है, स्टाफ के 67 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं और पिछले तीन साल से अधिक समय से जरूरी मानसिक रोग की दवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। जर्जर हो चुकी बुनियादी सुविधाओं के सहारे चल रहा यह सिस्टम उस राज्य में मरीजों को संभाल रहा है, जहां मानसिक बीमारी का बोझ राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है।

कैग के अखिल भारतीय परफॉर्मेंस ऑडिट के अनुसार, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 13.9 प्रतिशत हिस्सा मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, जो देश के

मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा

- मध्य प्रदेश में मानसिक रोगियों की दर 13.9 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 10.7 प्रतिशत से ज्यादा है।
- सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 1 से 36 महीने तक दवाएं गायब रहीं।
- पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 47 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक उपकरणों की भारी कमी।
- 2021-24 के दौरान राज्य के दोनों सरकारी मानसिक अस्पतालों में एक भी रेडियोलॉजिस्ट तैनात नहीं।
- विभिन्न संस्थानों में 13 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक पद रिक्त।

राष्ट्रीय औसत (10.7 प्रतिशत) से काफी अधिक है। इसका मतलब है कि राज्य में हर 100 में से लगभग 14 लोग मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है।

राज्य प्राधिकरण और निगरानी तंत्र की नाकामी- कैग की रिपोर्ट ने स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। गठन में ढाई साल से ज्यादा की देरी के बाद बनी यह अथॉरिटी विशेषज्ञों की कमी के कारण जुलाई 2025 तक केवल आंशिक रूप से ही काम कर पाई। स्थिति यह है कि राज्य के 163 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से सिर्फ 82 ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि बाकी 81 संस्थान बिना किसी रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, इंदौर और ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के खाने पर रोजाना मात्र 48 और 65 रुपये ही खर्च किए जा रहे हैं, जो मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों से काफी कम है।

कागजों पर नियम, जमीन पर भारी लाचारी

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 के तहत मुफ्त दवाएं देने का प्रावधान है और राज्य की ड्रग पॉलिसी में बफर स्टॉक रखना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। ऑडिट में यह भी पाया गया कि राज्य के दोनों प्रमुख सरकारी मानसिक अस्पतालों में 2021 से 2024 के बीच एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, जिसके चलते मजबूरन मनोचिकित्सकों को खुद ही एक्स-रे और अन्य जांच रिपोर्ट देखनी पड़ रही थीं।

अस्पतालों में पीने के साफ पानी, अलग वार्ड, पर्याप्त बिस्तरों और साफ-सुथरे शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी भारी अभाव है। स्थिति इतनी खराब है कि निरीक्षण किए गए किसी भी केंद्र में नाबालिगों के रहने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी।

'मन की बात' में गूंजा सीधी का जल संरक्षण मॉडल

पीएम मोदी ने की तारीफ, 1500 नए तालाबों से बदली गांवों की तकदीर

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान पर चर्चा के दौरान प्रदेश के सीधी और नरसिंहपुर में जलसंरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख किया तथा राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश के सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए गए है, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश कि हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से अपने आस-पास तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लेने और पानी की हर बूंद बचाने के अभियान में साथ आने का आव्हान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज बचाई गई हर बूंद, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी जिले की पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में कंचना घाट पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण

सिंह कुशवाह तथा जनप्रतिनिधि और स्थानीयजन उपस्थित थे।

जहां जब बारिश गिरे-पानी को वहीं सहेजिए- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां जब बारिश गिरे, पानी को वही सहेजिए, इसीलिए 4 जुलाई से देशभर में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज, पुराने जल स्त्रोतों के पुर्नजीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही हैं। गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं हर जगह लोगों ने बढ़-चढ़ कर भागीदारी की है । कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुओं और बावड़ियों को फिर से जीवंत किया जा रहा है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हुए कार्यों के उत्साह जनक परिणामों का भी उल्लेख किया। राज्यसभा सांसद श्री महेश केवट, विधायक निवाड़ी श्री अनिल जैन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

सास गिरिबाला सिंह को झटका

स्पेशल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, गवाहों से छेड़छाड़ का लगा आरोप

भोपाल (नप्र)। देश भर में सुर्खियां बने मॉडल ट्विशा शर्मा संदिग्ध दहेज हत्या केस की मुख्य आरोपी सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। उन्होंने भोपाल की स्पेशल कोर्ट में खुद को महिला व स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में सीबीआई ने तर्क प्रस्तुत करते हुए तगड़ा विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

जानकारी अनुसार राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने पूर्व अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत व दहेज हत्या मामले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने मामले की मुख्य आरोपी और मृतका की सास पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

फांसी के फंदे पर मिली थी ट्विशा, सास-पति गिरफ्तार

बता दें कि बीती 12 मई 2026 को भोपाल स्थित आवास अपनी ससुराल में पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा ससुराल में फांसी पर लटकी पाई गई थीं। घटना के बाद परिजनों की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, जो रिटायर्ड जज हैं उनको व ट्विशा के पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था।

बचाव पक्ष ने दिया उम्र और बीमारी का हवाला

दूसरी ओर, बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि गिरिबाला सिंह एक बुजुर्ग महिला हैं और बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनका जेल में इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही, उनकी 100 वर्षीय बीमार मां भी देखभाल के लिए उन पर ही निर्भर हैं। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि आरोपी को नियमित पेंशन मिलती है, इसलिए दहेज मांगने का आरोप निराधार है।

जांच व सबूत को प्रभावित करने के लगे आरोप

जानकारी अनुसार मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि, आरोपी पूर्व जज ने जांच के दौरान अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया था। पहीं आरोपी ने मामले से जुड़े सीसीटीवी टेक्नीशियन और सैलून संचालक से संपर्क कर जांच को प्रभावित करने तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस याचिका से पहले हाईकोर्ट 27 मई को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर चुका है। सीबीआई ने कोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सख्त एतराज जताया था।

भोपाल में 3435 जर्जर मकान खतरनाक, कागजों पर नोटिस

जमीनी हकीकत में सिर्फ 1 प्रतिशत पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में मानसून के दौरान बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। भोपाल नगर निगम ने शहर भर में हजारों जर्जर इमारतों की पहचान तो कर ली है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हाल ही में कोटवाली के पास 90 साल पुराने एक जर्जर मकान के ढहने की घटना ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है।

निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में कुल 3,435 जर्जर मकान चिन्हित किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 72 प्रतिशत इमारतें सरकारी विभागों के अधीन हैं, जबकि 28 प्रतिशत निजी स्वामित्व वाली हैं। इसके बावजूद प्रशासन की सुस्ती आम जनता की जान पर भारी पड़ रही है।

नोटिस का खेल और कागजी कार्रवाई- हर साल मानसून से पहले जर्जर मकानों का सर्वे कराया जाता है और मालिकों या विभागों को नोटिस थमा दिए जाते हैं। इस साल भी निगम ने करीब 64 प्रतिशत इमारतों को नोटिस जारी किए, लेकिन जमीनी स्तर पर डिमोलिशन का काम सिर्फ एक प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। पुराने शहर और घनी आबादी वाले इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं।

इस साल डिमोलिशन का आंकड़ा- मात्र एक प्रतिशत के आसपास

ऐशबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में सैकड़ों मकानों को सालभर पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका है। यहां रहने वाले परिवार आज भी बिना किसी सुरक्षा के उन जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम का यह सालाना नोटिस चक्र सिर्फ औपचारिकता है, जिससे फाइलों में तो काम पूरा हो जाता है, लेकिन बारिश में गिरने वाले मकानों का खतरा टलता नहीं है।

कानूनी पेच और निगम की सफाई

नगर निगम का तर्क है कि ज्यादातर जर्जर इमारतें कोर्ट में पेंडिंग मामलों और कानूनी विवादों में फंसी हुई हैं। इसी वजह से कार्रवाई या तो अदालत के दखल के बाद होती है या फिर जब जनता की सुरक्षा पर तुरंत खतरा मंडराने लगता है। ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग बताती है कि पुराने भोपाल के तंग बाजारों और गलियों में लोग हर दिन डर के साये में जीने को मजबूर हैं, और प्रशासनिक सुस्ती किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है।

संपादकीय

प्रधान के इस्तीफे की अंतर्कथाएं

अब पूर्व हो चुके केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. धर्मेन्द्र प्रधान के कॉकरोचों के दबाव में इस्तीफा देने की अंदरूनी कहानियां सामने आने लगी हैं। बताया जाता है कि प्रधान स्वयं दो बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, लेकिन उसे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि त्यागपत्र का मतलब जिम्मेदारी से भागना होगा। मोदी सरकार और भाजपा का यह आकलन ही उसके गले की हड्डी बन गया और छात्र आंदोलन सुरसा की तरह फैलता चला गया। इस्तीफे के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आधी रात को इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर आंदोलनकारी जेन ज़ी को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। उल्टे आंदोलनकारियों की तीन प्रमुख मांगों में मंत्री के इस्तीफे की मांग ही मुख्य हो गई। अंत में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और आरएसएस का भी मानना था कि अगर अभी इस्तीफा नहीं हुआ तो पूरा मामला हाथ से निकल जाएगा। आईबी की रिपोर्ट भी यही कह रही थी। सरकार को चिंता इस बात की थी कि अगर यह आंदोलन नेपाल की तर्ज पर हिंसक और बेकाबू हो गया तो भारी नुकसान होगा, सरकार की बदनामी होगी, सो अलग। इसके पहले सरकार ने आंदोलन में फूट डालने की कोशिश भी की। आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के साथ अलग से बात कर समझौता किया गया, लेकिन आंदोलन के सूत्रधार अभिजीत दीपके से कोई बात नहीं की गई। एबीवीपी के छात्रों को भी आंदोलन में शामिल कराने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी नाकाम रही। दूसरी तरफ आंदोलन और तेज होता गया। दूर दराज से लड़के-लड़कियां इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। विपक्षी पार्टियों ने भी आंदोलन को पूरा समर्थन दे दिया। हालांकि आंदोलनकारी छात्रों ने विपक्ष को अपना मंच हाईजैक नहीं करने दिया। राहुल गांधी तो अंत तक जंतर मंतर नहीं गए। आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने आंदोलनकारियों से बात करने का इशारा किया। बताया जाता है कि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा होगा, यह जानकारी केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और आरएसए को थी। सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहे केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह को भी इसकी जानकारी बाद में मिली। इससे पहले किसान आंदोलन के हिंसक होने के बाद सरकार ने बिल वापस लिए थे। आंदोलनकारियों के सामने झुकने का ये दूसरा मौका है। आंदोलनकारी युवा प्रधान के इस्तीफे को सरकार का झुकना बता रहे हैं तो भाजपा के सूत्रों का कहना है कि यह इस्तीफा सरकार की रणनीति का हिस्सा है। यानी दो कदम आगे जाने के लिए एक कदम पीछे खींचने की रणनीति। जहां तक इस्तीफे की बात है तो किसी आंदोलन के दबाव में ऐसा पहली बार हुआ है। यहां तक कि किसान आंदोलन के बाद सरकार ने तीन विवादित कृषि कानून वापस लिए थे, लेकिन इस्तीफा किसी का नहीं हुआ था। बहरहाल आंदोलन समाप्त हो गया है। आंदोलनकारी छात्र अपने घरों को लौट गए हैं। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार छात्रों की बाकी दो मांगों का क्रियान्वयन कब और कैसे करती है। इन दो मांगों में छात्रों पर लाठियां बरसाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई तथा नीट पेपर लीक होने के बाद हताशा में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रू. का मुआवजा देना शामिल है। अगर सरकार इन वादों से मुकरी तो जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है। मोदी सरकार ही क्या, कोई भी सरकार युवाओं को इस तरह नाराज नहीं कर सकती। क्योंकि आने वाले कई सालों तक वोटर रहने वाले हैं। दूसरे, जो मुद्दा छात्र उठा रहे थे, वो बिल्कुल जायज था।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

प्राकृतिक संपदा को बचाना मतलब मानवता बचाना

वेदांता ग्रुप के मालिक उद्योगपति श्री अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने देश में कुछ समय पूर्व से हो रहे तेल के संकट जो अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण हो रहा था, का उल्लेख करते हुए दुख व्यक्त किया, और लिखा है कि एक ऐसा युद्ध जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, उसकी कीमत देश को रॉ मटेरियल की कमी के चलते उठाना पड़ी है। उन्होंने यह एक वाजिब सवाल उठाया है कि हम देश की जरूरत का 90 प्रतिशत तेल, 95 प्रतिशत कॉपर, 99.5 प्रतिशत सोना विदेश से क्यों आयात करते हैं, जबकि धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि 40 साल इस उद्योग में काम करते हुए वे यह मानते हैं कि भारतीय भूगर्भ दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इसी लेख में उन्होंने अपने जीवन को उद्धत करते हुए बताया है कि 19 वर्ष की उम्र में वे बिहार से मुंबई आये थे, जीरों से कोराबार शुरू किया और उस समय इनके कोई संपर्क नहीं थे, कोई गॉडफादर नहीं थे तथा उन्होंने याने वेदांता कंपनी ने सरकार की निजीकरण योजना के तहत हिंदुस्तान जिंक व बालको खरीदा, हालांकि उन्हें दुख है कि इनके शत प्रतिशत शेयर अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। देश की खनिज आत्मनिर्भरता के लिये उन्होंने बड़े पैमाने पर देश के खनिज उत्पादन तेल और गैस के उत्पादन, लोहे का उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

यह तथ्य है कि श्री अनिल अग्रवाल के आर्थिक साम्राज्य की वृद्धि श्री अंबानी, श्री अडानी के समान चमत्कारिक हुई है। परंतु उनके दावों व निष्कर्षों की तार्किक पड़ताल जरूरी है। उन्होंने यह नहीं बताया जब वे बिहार से चलकर मुंबई आये थे तो उनके पास कितनी पूंजी थी। सरकार के निजीकरण कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान जिंक व वालको के शेयर खरीदे तब उसके लिए पूँजी कहां से आई और उन कंपनियों के शेयर होल्डर उस जमाने में कौन लोग थे? क्या हिंदुस्तान जिंक व बालको के क्रमशः 74 प्रतिशत, और 51 प्रतिशत शेयर्स उन्हें मुफ्त में प्राप्त हुए थे, जब उनका कोई संपर्क ही नहीं था तो उन्हें इतनी बड़ी धन राशि कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनकी करोड़ों की कोई लॉटरी खुली हो। आम चर्चा तो यह है कि देश के भ्रष्ट राजनेता और कुछ बड़े उद्योगपति अपने विश्वस्त लोगों से कारखाने खड़े कराते हैं, उसमें बेनामी शेयर्स की राशि डालते हैं, जो एक प्रकार का निवेश होता है और फिर प्रतिवर्ष प्रीमियम के नाम पर बड़ी-बड़ी राशियां लेते रहते हैं, जिससे पूंजी बढ़ती है और राजनेताओं के भारी भरकम खर्च भी चलते हैं। श्री अनिल अग्रवाल ने ब्रिटेन से ओएनजीसी के तेल व गैस के लिये पूंजी प्राप्त की। जापान के मितसुई से सेसा गोवा आयरन अयस्क खरीदा। वे कहते हैं कि हर इस अधिकरण के पीछे एक ही सपना था कि प्रोडक्शन इतना बढ़ाया जाए कि देश आयातक नहीं निर्यातक बन जाये। वे अपनी पीठ यह कहकर थपथपाते हैं कि जिंक का उत्पादन 10 गुना, एल्यूमीनियम का 20 गुना बढ़ाया जिससे 1000 से अधिक कंपनियां खड़ी हुईं और इन 10 वर्षों में वेदांता ने सरकारी खजाने में 4.5 लाख करोड़ रुपया दिया।

श्री अनिल अग्रवाल को मैं बताऊँ कि पिछले लगभग 30-40 वर्षों में जापान और चीन ने भारत से लोह अयस्क खरीदा तथा उसे समुद्रतल के नीचे डंप किया। जबकि उनके पास पर्याप्त लोहा था और उन्हें बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। परंतु ये देश ज्यादा समझदार व राष्ट्रभक्त है कि उन्होंने अपने देश के खनिजों को सुरक्षित रखने और उनका भंडार बढ़ाने के लिये उपाय किये। वे जानते हैं कि खनिज के भंडार धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे और इसीलिये उन्हें यथा संभव बचाया जाये। परंतु भारत की सरकार वैश्वीकरण के प्रभाव में इतनी ग्रस्त रही है कि उन्होंने कभी देश के व्यापक हित को नहीं सोचा। उनने यह नहीं सोचा कि जो खनिज हम निकालकर बेचेंगे यह दोबारा पैदा नहीं होगा। अगर यह खनिज के भण्डार देश में हैं तो देश की प्रकृति की देन है जिसे ईश्वरीय देन भी कहा जा सकता है। यह भण्डार न किसी सरकार ने बनाये और न ही किसी वेदांता ने। आज आप इन्हें खोदकर, उनका निर्यात कर सकते और कुछ संपन्न हो सकते हैं परंतु यह संपन्नता स्थाई नहीं हो सकती। 19वीं सदी में जिन क्षेत्रों में कोयला निकला था उनमें से आज कितनी ही कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं और स्थिति यह है कि हमें अपनी पूर्ति के लिये कोयला आयात करना पड़ रहा है। देश में जहां-जहां कोयले के भण्डार थे और उनका खनन हुआ निसंदेह सरकार के खजाने में पैसा आया, महानगरों में, कारखानों को बिजली पहुंची, उद्योगपतियों की तिजोड़िया भरी, परंतु जिन गरीबों की जमीन के नीचे कोयला निकला, या जिंक, एल्यूमीनियम, तांबा आदि निकला वह गरीब तो विस्थापन के शिकार हो गये। देश के चार छह उद्योगपति अरबपति से खरबपति बन गये, बीच के दलाल, ठेकेदार और राजनेता करोड़पति बन गये परंतु लगभग 30 करोड़ लोग इस विस्थापन के शिकार होकर, भुखमरी, बीमारी व गरीबी के समुद्र में फेंक दिये गये।

श्री अनिल अग्रवाल की कंपनी का विकास जहां राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हक में है परंतु वह देश के लिये अनुकूल नहीं है। वह लिखते हैं कि जिस प्रकार रियोटिन्टो और बीएचपी ने आस्ट्रेलिया के विकास के लिये जो भूमिका अदा की वही भूमिका वेदांता भारत के लिये करना चाहता है। रियोटिन्टो एक वैश्विक सोना खदानें खोजने वाली कंपनी है और उसने आस्ट्रेलिया के सोने व खनिजों को खोजकर अपनी पूंजी में लाखों गुना का इजाफा किया है परंतु इससे आस्ट्रेलिया की वास्तविक स्थिति बहुत मजबूत नहीं हुई। चूंकि आस्ट्रेलिया में जमीन अधिक व आबादी कम है अतरू इन खनिज उत्खनन के दुष्प्रभाव पर चर्चा कम हुई, पर वह दिन आने वाला है कि जब आस्ट्रेलिया की सभी खजिन संपदा लुट जायेगी और वह दूसरों का मोहताज बन जायेगा। श्री अनिल जी कहते हैं कि जब देश में उद्योग तकनीक विशेषज्ञ व वित्त नहीं था तब वेदांता ने विदेश से 35 अरब डॉलर जुटाकर भारत में निवेश किया। अनिल जी जरा बतायें, 10 सालों में उन्होंने सरकारी खजाने में 4.5 लाख करोड़ दिये हैं, तब वेदांता के खजाने में क्या 20 लाख करोड़ रुपये से कम जमा हुए हैं? दुनिया के खनिज पूंजीपतियों ने वेदांता के माध्यम से 35 अरब डॉलर की पूंजी लगाई थी, क्या उन्होंने अभी तक 400 अरब डॉलर से कम मुनाफा कमाया है? रियोटिन्टो ने आस्ट्रेलिया को न विकसित बनाया, न मजबूत बनाया बल्कि वास्तविक रूप में गरीबी के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। खनिज जो स्थाई संपत्ति होती है वह भी चली गई और लाभ एक दो कंपनियों के खाते में पहुंच गया। अनिल जी लिखते हैं कि दुनिया के अधिकांश विकसित देश अपने प्राकृतिक स्त्रोत से बने हैं जबकि तथ्य यह है कि प्राकृतिक स्त्रोतों या खनिजों के आधार पर बने विकसित देश कुछ ही दशकों में बर्बादी के मुंह में फँस जाते हैं।

जहां तक उन्होंने दस लाख बैरल तेल प्रतिदिन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसे वह निर्यात भी करेंगे क्योंकि उनकी चिंता तो तेल और गैस के आयात के नाम पर देश को भयभीत करने की है। मेरी राय में तेल के मामले में भी भारत आसानी से आत्मनिर्भर बन सकता है, बर्शते वह अपने तेल की फिजूलखर्ची कम करे। जैसा कि हम कहते रहे हैं कि एक परिवार एक कार का कानून बने, अगर वह बन जाये तो देश में औसतन प्रतिदिन 100 करोड़ लीटर व माह में 3000 हजार करोड़ लीटर और साल में 36000 करोड़ लीटर तेल जिसकी कीमत 36 लाख करोड़ रुपये होगी वह बच सकती है। हमारे तेल के भण्डार भी खाली नहीं होंगे। अनिल जी कहते हैं कि सरकारों को रेवेन्यू माइंडेड नहीं, प्रोडक्शन माइंडेड होना चाहिये। याने एक प्रकार से वह उद्योगपतियों की सरकार चाहते हैं जो उत्पादन कर्ताओं को सभी वैधानिक बंधनों से मुक्त करे यहां तक कि सरकार की अनुमति के बगैर स्वरू प्रमाणन की व्यवस्था हो। मेरी राय में सरकारों को न रेवेन्यू माइंडेड होना चाहिए, न प्रोडक्शन माइंडेड, बल्कि उन्हें प्रकृति संरक्षक, खनिज संरक्षक और मानवीय तथा मानवीय विकास की दृष्टि का होना चाहिए। प्रकृति का दोहन न हो, बल्कि न्यूनतम व जरूरी उपयोग के विकास में समानता हो। उन्होंने खुद ही लिखा है कि उनके पारिवारिक गुरु वृंदावन के स्वामी शारदानंद जो मानव सेवा संघ में एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। उन्होंने उनसे कहा था संपत्ति है, उसे समाज के लिये उपयोग में लाओ और संपत्ति का होने का अर्थ क्या है? एक प्रकार से उन्होंने श्री अनिल अग्रवाल को संकेत दिया है कि जो संपत्ति का संचय किया है, उसे समाज को वापस लौटाओ। मेहनत पूंजीपति भी करते हैं और मजदूर भी करते हैं। पूंजीपति दिमागी मेहनत करते हैं, आमतौर पर भ्रष्टाचार का कौशल अपनाते हैं और उससे अमीर बनते हैं। परंतु मजदूर शरीर का श्रम करता है, पसीना अधिक बहाता है और खुराक व सुविधा कम पाता है। इस विषमता को संतुलित करना और मिटाना होगा। हालांकि अपने इसी लेख में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा उनकी हौसला अफ्जाई को इन शब्दों में दर्ज किया है कि श्यही मेरे जीवन की प्रेरणा है। वे कहते हैं कि श्उनके सुझावों से भारत दुनिया में सर्वाधिक राजस्व देने वाला क्षेत्र बनेगा, सुधार और प्रगति होने से बेरोजगारी दूर होगी, देश आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित राष्ट्र बनाने का माध्यम बनेगा, जैसा कि सपना श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देखा है। तथ्य यह यह है कि, प्रधानमंत्री जी के सपने से बेरोजगारी बढ़ी है, विदेशी कर्ज बढ़ा है, देश तकनीक और अनेकों मामलों में पर निर्भर हुआ है। आशा है अनिल अग्रवाल जी कभी मेरे सुझावों पर भी विचार करेंगे। राष्ट्र के विकास के जो रास्ते महात्मा गांधी व डॉ लोहिया जी ने बताये थे, उनका भी अध्ययन और उन पर भी मनन करेंगे।

जंतर-मंतर-आंदोलन

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आक्रोश का प्रदर्शन या प्रतिरोध का कार्निवाल

आंदोलन को पहली सफलता छत्तीस दिन बाद मिली। छत्तीस दिन कम नहीं होते। कैलेंडर के पन्नों के फड़फड़ाने के साथ ही आंदोलन हाँफने लगता है। धैर्य चुकने से आंदोलन बेपटरी भी हो सकता है, लेकिन जंतर-मंतर का संघर्ष डिगा नहीं, इस दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया फिर कर्तव्यच्युत दिखा, किंतु सोशल मीडिया सशक्त अवतार के रूप में सामने आया। गैर-पेशेवर किरदारों ने पल-पल की तस्वीरें जुटायीं और हर कोण से चीजों को पेश किया। इस आंदोलन से मुझे जेपी आंदोलन और अपने भूमिगत दिनों की याद हो आयी। मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' और डॉ. धर्मवीर भारती की 'मुनादी' कविता की याद आई। मुझे ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां याद आईं, लेकिन जंतर-मंतर आंदोलन से मुझे नये सबक मिले। यह पाठ रगों में रक्त का संचार करता है कि जेन-जी या युवा पीढ़ी सचेत है। एक बारगी दृश्यों को याद करें। कोई झंडा या बैनर नहीं, मगर बच्चे हैं कि चले आ रहे हैं। स्वतंत्र-भारत के इतिहास में यह पहला आंदोलन है, जिसमें लड़कियों ने इतनी तादाद में स्वयं स्फूर्त शिरकत की।

अंततः धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन यह जेन-जी प्रणीत आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति है। यह युवा वर्ग के आंदोलन के कथानक का अल्पविराम है। प्रथम और आगामी चरण के मध्यवर्ती अंतराल में स्वाभाविक तौर पर हमें यह सोचना होगा कि हम इसे क्या कहें - आक्रोश का अपूर्व उत्सव अथवा प्रतिरोध का कार्निवाल? बिलाशक यह बापू के दिये 'यंत्र' और 'मंत्र' (जंतर-मंतर) की ऐतिहासिक जीत है, लेकिन इसका अपूर्व चरित्र इसके लिये नयी संज्ञा की मांग करता है।

गौर करें तो शब्दकोश में इसके लिये कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। यह आंदोलन भी है और आक्रोश की अभिव्यक्ति भी। मगर इसका अंदाज अलग है। इसका चरित्र औपनिवेशिक युग और स्वांत्रयोत्तर काल के इस तरह के सामूहिक उपक्रमों से सर्वथा भिन्न है। यकीनन जेन-जी आंदोलित और उद्वेलित है। उसकी मुष्ठियां भिंची हुई हैं, लेकिन उसके भीतर किसी के लिये घृणा, बैर अथवा वैमनस्य नहीं है। जंतर-मंतर पर उसका हुजूम मतवालों की अलमस्त टोलियों सा नजर आता है। आंदोलन का यह पैटर्न विश्व में नया है। दिल्ली का जेन-जी आंदोलन ढाका या काठमांडू और बरसों पहले के बीजिंग के थ्येन-आनमन आंदोलन से अलहदा है। वह हिंसक या अराजक नहीं है। जंतर-मंतर का आंदोलन गांधीवादी मूल्यों की महत्ता और प्रभाव की दिलचस्प मिसाल है। इसकी रगों में अन्याय के प्रतिकार के साथ ही सत्य और अहिंसा की भावना प्रवाहमान है। मजेदान बात है कि इसका अंदाज या चरित्र कुछ ऐसा है कि शब्दकोश न्यून हो गया है। क्या इसे आक्रोश का उत्सव कहें? नहीं, उत्सव या जश्न तो अंतिम चरण की सफलता के बाद का प्रसंग होता है। तो क्या हम इसे प्रतिरोध का कार्निवाल कह सकते हैं?

आंदोलन को पहली सफलता छत्तीस दिन बाद मिली। छत्तीस दिन कम नहीं होते। कैलेंडर के पन्नों के फड़फड़ाने के साथ ही आंदोलन हाँफने लगता है। धैर्य चुकने से आंदोलन बेपटरी भी हो सकता है, लेकिन जंतर-मंतर का संघर्ष डिगा नहीं, इस दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया फिर कर्तव्यच्युत दिखा, किंतु सोशल मीडिया सशक्त अवतार के रूप में सामने आया। गैर-पेशेवर किरदारों ने पल-पल की तस्वीरें जुटायीं और हर कोण से चीजों को पेश किया। इस आंदोलन से मुझे जेपी आंदोलन और अपने भूमिगत दिनों की याद हो आयी। मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' और डॉ. धर्मवीर भारती की 'मुनादी' कविता की याद आई। मुझे ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां याद आईं, लेकिन जंतर-मंतर आंदोलन से मुझे नये सबक मिले। यह पाठ रगों में रक्त का संचार करता है कि जेन-जी या युवा पीढ़ी सचेत है। एक बारगी दृश्यों को याद करें। कोई झंडा या बैनर नहीं, मगर बच्चे हैं कि चले आ रहे हैं। स्वतंत्र-भारत के इतिहास में यह पहला आंदोलन है, जिसमें लड़कियों ने इतनी तादाद में स्वयं स्फूर्त शिरकत की। कोई 'इंसेंटिव' नहीं, कोई फंडिंग नहीं। वे अभिभावकों को बिना बताये छिपकर आईं। निडर और निश्चिंत। गांधी ने और क्या किया था। उन्होंने अमीर-गरीब, मजदूर-किसान सबको योद्धा में बदल दिया था। उनकी जंग सत्य और सत्ता की जंग थी। गांधी जिसे आत्मबल कहते थे, वह इस आंदोलन में सतत देखने को मिला। जाति-धर्म, जेंडर, छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं। कोई छीनाझपटी, छेड़छाड़ का प्रसंग नहीं। देखें तो लगे कि बच्चे दिलजोई या तफरीह करने चले आ रहे हैं। लेकिन नहीं, वे खोट और खुरंटग्रस्त शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। आंदोलन की तासीर देखिये। दमन, प्रताड़ना और बेरूखी के बावजूद पुलिसकर्मियों तक को गुलाब के फूल, पानी बाटलें और फूड पैकेट ऑफर किये गये और ऐसे संबोधन व नारे सुने गये, जिससे वे शर्मसार हो जायें। प्रदर्शनकारियों के लिये फूड, पानी बॉटल्स, डस्टबीन और प्री सेफ के दूर-दूर यहां तक कि विदेशों से ऑर्डर किये गये। धरना स्थल पर गाने-बजाने, पैरोडी मिमिक्री और कोरस-गान के दृश्य थे। बापू से जब एक विदेशी संवाददाता ने पूछा था कि बापू आपका अपने दुश्मनों के लिये क्या संदेश है, तो बापू ने कहा था -'मेरा तो कोई दुश्मन हीं नहीं है।' आंदोलन ने लोगों के मन से डर या हौबा निकाल दिया।

इस आंदोलन ने तस्दीक कर दी कि गांधी इस महोदश की रगों में है। बापू ने कोटि-कोटि जनों में जो लौ बाली थी, वह अभी बुझी नहीं है। सत्ता ने गलतियां कीं। उसने संवाद की अहमियत को बिसरा दिया। 20 जुलाई को पुलिस की बर्बरता ने सत्ता की छवि कलुषित की और आग में घी का काम किया। बच्चों की साहसिक सहनशीलता ने माँ-पिताओं और बड़े-बूढ़ों को जंतर-मंतर पहुंचने को प्रेरित किया। बेटे-बेटियों का आचरण धिक्कार का हेतु बना। इस आंदोलन ने कइयों की कलई खोल दी। इसमें अव्वल रहे सोनम वांगचुक। निजी अस्पताल में सत्तापक्ष के हाथों जूस पीकर उन्होंने जिस प्रकार अनशन तोड़ा, उससे उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। रही सही कसर उनके इस आशय के बयान ने पूरी कर दी कि वह लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सिन्हा के कहने पर सीजेपी के आंदोलन में शरीक हुये।

राहुल और अखिलेश के बारे में वांगचुक-दंपत्ति के बयान भी गैर जरूरी थे। जहां तक सीजेपी का प्रश्न है, सीजेआई की टिप्पणी से यकबयक जनमी सीजेपी और उसके नेताओं को अभी और इम्तहान देने होंगे। जेपी और अन्ना आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में प्रतिपक्ष और बौद्धिकों के मन में ढेर सारे संशय है। यह अकारण नहीं है कि केजरीवाल को आंदोलनकारियों की ओर से कोई भाव नहीं मिला, जबकि जेएनयू की नेहा बोरा संघर्षचेता नेत्री बनकर उभरीं।

राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे दौर में साहस और सतर्कतापूर्वक कदम उठाये, से उनका सार्थक संवाद उन्हें भविष्य में जमीन मुहैया कर सकता है। राहुल सुर्खियों में रहे, अलबत्ता उन्होंने औरों को 'स्पेस' दिया और फ्रेम में अकेले रहने से परहेज बरता। वह आगे आंदोलन के हिमायती हैं। मोदी को भारत का अतीत बताते हुये उनकी यह टिप्पणी आगे भी कौंधती रहेगी कि पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। क्या अतीत भविष्य का मुकाबला कर सकता है?

यह जंतर-मंतर आंदोलन की सफलता है कि उसने सारे देश को उद्वेलित कर दिया है। प्रदर्शन की आंच विदेशों तक में पहुंच गयी है। बौद्धिक प्रायः जेन-जी के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार कौंसिल उनके साथ है। दिल्ली के वेधशाला ने भारतीय राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है।

दिल्ली पुलिस की किरकिरी हुई है। प्रसंग अवांतर है। पुणे में एसपी कांबले ने पुलिस बल को युवकों पर कतई बल प्रयोग नहीं करने का ऐलान किया तो छात्रों ने 'दिल्ली पुलिस हाय-हाय, पुणे पुलिस आई लव यू' के नारे लगाये। यह 'फ्यूजन' का दौर है। जेन-जी के आंदोलन में भी कई चीजें घुलमिल गयी हैं। जंतर-मंतर के असमाप्त आंदोलन का चरित्र भी इसी 'सायुज्य' की देन है। उसमें सत्य भी है, सविनय अवज्ञा भी है, अन्याय के प्रतिकार का संकल्प है और प्रेम और अहिंसा भी। जेन-जी भारत का भविष्य है। उसके सपने, आशाएं और उसकी चिंताएं सारे भारत के लिए मायने रखती हैं। रिश्तों का यह कथानक मुझे मक्सीम गोर्की की कहानी 'सीला मातिरी' (मातृशक्ति) की याद दिलाता है। सत्य और सत्ता की मुसलसल जंग में अभी यह देखा जाना शेष है कि आंदोलन के आगे के चरणों में सत्ता क्या रवैया अख्तियार करती है?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

डॉ. कलाम की पुण्यतिथि पर विशेष

शिवकुमार शर्मा

लेखक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

तपोनिष्ठ राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक

मानवता के सच्चे सेवकों के लिए ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, लगन,अटूट श्रम, सच्ची राष्ट्रभक्ति ही धर्म है,कर्म है और उनकी विद्वता व राष्ट्र सेवा में समर्पण ही उनका का सबसे बड़ा अलंकरण-आभूषण होता है। ऐसे संत-फक्कड़ों के लिए अमीरी-गरीबी, धर्म, मजहब और पंथ कोई मायने नहीं रखते, दुविधायें-सुविधायें कहीं आढ़े नहीं आती है, ऐसे दृढ़ संकल्पी इन सबसे परे होते हैं तथा वे ही फर्श से अर्श या सिफर से शिखर तक की यात्रा पूरी कर अनन्तकाल तक समाज के प्रेरणापुंज बने रहते हैं। इसका जीवन्त उदाहरण थे भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब.उनका पूरा नाम अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए बचपन में अख़बार बेचने का काम किया। छोटी आयु में कठिन परिश्रम करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, किंतु इसी संघर्ष ने उन्हें आत्मनिर्भर और कर्मठ बनाया। प्रारम्भिक शिक्षा रामेश्वरम् में प्राप्त करने के बाद उन्होंने । मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। वे चयन प्रक्रिया में नौवें स्थान पर रहे, जबकि केवल आठ अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुःख था किंतु उन्होंने निराश न होकर वैज्ञानिक बनने का मार्ग चुना और आगे चलकर पूरे देश का गौरव बने।वर्ष 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.)में वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरम्भ किया और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से जुड़ गए। वहाँ उन्होंने भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान एस एल वी-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके माध्यम से 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलता - पूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया।

डॉ. कलाम ने भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल विकास हुआ, जिसके कारण उन्हें 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' कहा गया।

वर्ष 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों में भी उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के लिए यह अद्भुत और अनुपम संयोग ही था कि स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेई जी प्रधानमंत्री थे उसी समय डॉ. कलाम वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 2007 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उनके पास निजी संपत्ति के नाम पर कुछ पुस्तकें, कपड़े, एक वीणा और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएँ ही थीं। उनका जीवन सादगी और नैतिकता का आदर्श उदाहरण था।अपनी सादगी, विनम्रता तथा युवाओं के प्रति विशेष लगाव के कारण वे 'जनता के राष्ट्रपति' के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए निरंतर प्रेरित करते थे।

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे शिक्षण, लेखन और युवाओं के मार्गदर्शन में सक्रिय रहे।कलाम साहब ने विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रनिर्माण और युवाओं के मार्गदर्शन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। वह कहते थे कि 'सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।' महान कर्मयोगी कलाम साहब ने यह करके दिखाया।

27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय उन्हें हृदयाघात हुआ वह महानायक हम से विदा हो गया । उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम, सादगी और राष्ट्रसेवा का अनुपम उदाहरण है।

डॉ.कलाम को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण,1990 पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि डॉ.सी सी रमन को 1952 में भारत रत्न से नवाजा गया था इसके पश्चात एक लंबे अरसे के बाद 1997 में किसी वैज्ञानिक को यह सम्मान प्राप्त हुआ।

न्याय और कानून

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

पर्यावरण की सुरक्षा करना हर हाल में जरूरी

भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने वाले प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के इस्तेमाल पर जोर देने के बजाए ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, जिनसे प्रदूषण न हो। किसी ऐसे वैकल्पिक मटेरियल का इतनी बड़ी संख्या में विसर्जन से जल निकायों में प्रदूषण होना तय है, भले ही राज्य की नीति अगले दिन मूर्तियों को हटाने की हो। प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियां आसानी से नहीं घुलती हैं। उन पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जहरीले होते हैं। जबकि, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इको-फ्रेंडली मूर्तियों को अपना चुके हैं। खासकर छह फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों में।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 16 जुलाई को प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणेश मूर्तियां बनाने वालों से पूछा कि क्या उनके व्यावसायिक फायदे पर्यावरण की सुरक्षा और समाज के व्यापक हितों से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की डिवीजन बेंच ने यह बात जनहित याचिका पर बहस के दौरान कही। इस याचिका में प्राकृतिक जल निकायों में प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियों के विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है, भले ही उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्ति बनाने वालों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से बात करते हुए न्यायालय ने कहा कि क्या लोगों के एक समूह का हित समाज के हित से ऊपर हो सकता है? न्यायालय ने निर्माताओं से प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने का भी आग्रह किया। न्यायमूर्ति गडकरी ने पूछा कि मूर्ति बनाने वाले प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के इस्तेमाल पर जोर देने के बजाय ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते जिनसे प्रदूषण न हो।

उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी ऐसे वैकल्पिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण न हो। बेंच ने इस तथ्य पर गौर किया कि पिछले साल पूरे महाराष्ट्र में प्राकृतिक जल निकायों में छह फीट से ज्यादा ऊंची 31,000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां विसर्जित की गईं। खंडपीठ ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विसर्जन से जल निकायों में प्रदूषण होना तय है, भले ही राज्य की नीति अगले दिन मूर्तियों को हटाने की हो। याचिकाकर्ता रोहित जोशी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की 2025 की नीति, जो प्राकृतिक जल निकायों में छह फीट से ज्यादा ऊंची प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति देती है, वह केवल मार्च 2026 तक लागू रहने के लिए थी। इसके बाद पूरी तरह से रोक लगाने की योजना थी।

उन्होंने कहा कि राज्य का रुख उसकी अपनी स्टडी के विपरीत है। इससे पता चलता है कि प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियां आसानी से नहीं घुलती हैं। उन पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जहरीले होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य नीति के तहत किए गए वादों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने वालों के संगठन की ओर से पेश अभिभाषक ने न्यायालय से आग्रह किया कि मौजूदा नीति को एक या दो साल और जारी रहने दिया जाए, ताकि लोगों की पसंद में धीरे-धीरे बदलाव हो सके। उन्होंने ऐसे आंकड़ों का जिक्र किया जिससे पता चलता है कि इको-फ्रेंडली मूर्तियों के ऑर्डर 2023 में लगभग 3,000 से बढ़कर पिछले साल 7.8 लाख हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच रातों-रात नहीं बदल सकती।

राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने न्यायालय को बताया कि बड़ी संख्या में भक्त पहले ही इको-फ्रेंडली मूर्तियों को अपना चुके हैं। खासकर छह फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों में। उन्होंने कहा कि पिछले साल विसर्जित की गई छह फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली 13,000 से ज्यादा मूर्तियां इको-फ्रेंडली थीं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के सामने मुख्य मुद्दा प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित की जाने वाली बड़ी मूर्तियों से जुड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 48 ए निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 ए में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। अधिनियम का विस्तार क्षेत्र। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य

सहित पूरे भारत में लागू है। केंद्र सरकार की शक्तियाँ इस अधिनियम में केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी।

अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, उसका निषेध या विनियमन करने की शक्ति तथा बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा प्रदूषक उत्सर्जन पर प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति या संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन। कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किये बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा। इसके अलावा प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ भी है।

अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने, ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिये किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देने तथा केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने का भी अधिकार है। सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति। किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिये केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकती है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करना या उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। इस अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण है। यहाँ व्यापक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है।

भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई। अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिये की गई थी, जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाता है। हालाँकि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के साथ को अपर्याप्त पाया गया है। इससे पर्यावरणीय मामलों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिये एक संस्था की मांग बढ़ गई। इस कारण पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके अलावा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण छह अन्य कानूनों के तहत दीवानी मामलों को भी सुलझाता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन, 1989, रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 1992, जैव विविधता पर कन्वेंशन, 1992, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1994, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट (1983) और द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन, 1994 में भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है।

डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन

कर्मयोगी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सृजन के मानवीय सरोकारों के पैरोकार

वसीम बरेलवी की शायरी को भारत और सीमाओं से परे, जो अपार लोकप्रियता मिली, वह अभूतपूर्व है। विस्तृत हिंदी और उर्दू की दुनिया प्रो वसीम बरेलवी की खूबसूरत शायरी और व्यक्तित्व की मुरीद है। पिछले दिनों प्रकाशित 520 पेज का ग्रंथ 'वसीम बरेलवी: जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा' संकलन प्रकाशित हुआ। संकलन में वसीम बरेलवी के रचनाकर्म, जीवन यात्रा, साक्षात्कार आदि साहित्यिक विधाओं में देश के शीर्ष शायरों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की 58 रचनाएं संकलित हैं। डब्ल्यू.बीएस फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रकाशित इस संग्रहणीय अंक के प्रकाशन का श्रेय कंप्यूटर इंजीनियर और साहित्य प्रेमी नीरज जैन को है। निस्संदेह, यह रचना बरेलवी के चाहने वालों के लिए संग्रहणीय है। नीरज जैन को अपनी चौथी संतान बताते हुए पुस्तक में वसीम बरेलवी आत्मीयता के साथ लिखते हैं '15 जनवरी 2023 में कार हादसे के बाद नीरज ने मेरी जैसी सेवा की, वैसा कोई आज्ञाकारी बेटा ही कर सकता है। मेरे बच्चे तो बाहर हैं, नीरज जी मेरी सांसों की पहरेदारी का दायित्व संभाले हुए हैं। मेरा रुआं-रुआं उनके और उनके परिवार के लिए दुआ है। ऐसी निस्वार्थ और समर्पित संतान जिसे मिल जाए वो क्यों न खूबी-ए-किस्मत पे अपनी नाज करे। खुदा इन्हें शाद रखे, आबाद रखे।'

नीरज बताते हैं कि वसीम साहब की शायरी को पढ़ने व सुनने का अनुभव ऐसा है कि जैसे हम एक साथ कबीर, मीर, गालिब और जायसी को पढ़ रहे हों। उनकी रचनाओं में इतनी गहराई और विविधता है कि वे समय व पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर जाती है। वसीम बरेलवी का सानिध्य मिलना मेरी जिंदगी की एक असाधारण घटना थी। मैंने वसीम साहब से बातचीत में महसूस किया कि वे जीवन के जटिल विषयों को कितनी सहजता व सरलता से समझा देते हैं। उनके सानिध्य ने मेरे दृष्टिकोण को इतना सकारात्मक बना दिया कि मेरे जीवन में अप्रत्याशित और अविश्वसनीय परिवर्तन हुए। साहित्यकारों व विभिन्न विधाओं में सृजनकारों की नीरज जैन द्वारा मदद का यह पहल किस्सा नहीं है। वे गाहे-बगाहे साहित्यकारों की मदद के लिये आगे आते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे शुष्क विषय के दक्ष इंजीनियर नीरज जैन साहित्य की सरस धारा के साथ लगातार डूबते-उतरते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे व कवि सम्मेलनों व साहित्यिक संवाद आयोजनों में वे बेहद सक्रिय रहते हैं।

नीरज जैन की साहित्यकारों की मदद की एक प्रेरणादायक घटना का जिक्र कला-संस्कृति के मर्मज्ञ रचनाकार राजेंद्र शर्मा बताते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को कथाकार बल्लभ डोभाल के 97वें जन्मदिन के अवसर पर कवि, लेखक, पत्रकार उनके नोएडा के सेक्टर 12 स्थित आवास पर बधाई देने पहुंचे तो पत्नी और जवान पुत्र के आकस्मिक निधन से दुखी बल्लभ डोभाल ने कहा कि मेरा जन्मदिन क्यों मना रहे हो, मैं तो सरकारी कागजों में मर चुका हूं।

बल्लभ डोभाल की यह बात सुन सभी स्तब्ध रह गये। कथाकार बल्लभ डोभाल ने दुखी मन से बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रकाशन विभाग उनके दो बाल उपन्यास चालीस सालों से प्रकाशित कर रहा है किन्तु

साल 2018 में प्रकाशन विभाग से उनके पते पर पत्र आया कि उक्त दो बाल उपन्यासों की रायल्टी देय है और चूंकि बल्लभ डोभाल की मृत्यु हो चुकी है, अत: रायल्टी की धनराशि प्राप्त करने के लिए उनके वारिस बल्लभ डोभाल डेथ सर्टिफिकेट और कोर्ट द्वारा प्रमाणित बल्लभ जी की वसीयत (विल) की प्रति प्रकाशन विभाग को भेज दें ताकि रॉयल्टी का भुगतान किया जा सके।

साहित्यकार राजेंद्र शर्मा बताते हैं जीवन भर कहानियां लिखने वाले बल्लभ डोभाल प्रकाशन विभाग के इस रवैये से इतने क्षुब्ध हुए कि आज तक उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया और प्रकाशन विभाग ने भी इस संबध में आगे कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा। गौरतलब बात यह है कि प्रकाशन विभाग आज भी उनके उपन्यास प्रकाशित कर बिक्री कर रहे है। कालांतर साहित्यकार राजेंद्र शर्मा ने नीरज जैन को बताया कि उम्र के दसवें दशक में चल रहे डोभाल जी जीवट के धनी हैं, पर अब वह पहले की भाँति चल फिर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में समाज और संस्थाओं को आगे आकर रचनाकारों का ख्याल रखना चाहिए।

घटना से गहरे आहत नीरज जैन ने महसूस किया कि यह सूचना भयावह है। बल्लभ डोभाल जी की साहित्य के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा है। उनकी कहानियां प्रेमचंद के पुत्र और 'कहानी पत्रिका' के संपादक श्रीपत राय प्रमुखता से प्रकाशित करते रहे। आखिर कैसे कोई संस्थान कैसे जीते जी किसी रचनाकार को मृत घोषित कर सकता है। निश्चय ही यह प्रकाशन विभाग की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इस घटना ने नीरज जैन को उद्वेलित किया। वे बल्लभ डोभाल के घर पहुंचे और जीवनोपयोगी वस्तुओं के साथ उनकी आर्थिक मदद की। उन्होंने प्रतिमाह उन्हें आर्थिक मदद देने की वायदा किया। विडंबना यह है कि डोभाल जी के पास एटीएम कार्ड व बैंक सुविधा नहीं है। अत: नीरज जैन ने हर माह उनकी मदद के लिए उनके पास जाने का फैसला किया। वे नियमित रूप से खाने पीने व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं देने उनके घर जाते हैं।

27 अक्टूबर 1977 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव कुरालसी में जन्मे नीरज जैन को पिता बिजेंद्र जैन व माता श्रीमती सावित्री जैन ने उच्च संस्कार व शिक्षा दी। दादा शिखर चंद जैन के आदर्शों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उप्र के बुढ़ाना व बड़ौत से प्रारंभिक पढ़ाई के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दक्षता के लिए एशिया के पहले इंजीनियरिंग संस्थान रुड़की विवि (अब आईआईटी रुड़की) व बिट्स पिलानी से एमसीए व एमएस में डिग्री हासिल की। फिर भारत सरकार के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में कंसल्टेंट के पद पर काम करते हुए परिवहन प्रोजेक्टों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। जैन जीवन दर्शन के अनुरूप परोपकार व साहित्य के प्रति गहरा अनुराग उनका विशिष्ट गुण हैं।

पिछले दिनों दिल्ली में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर'का मासिक कार्यक्रम 'डायलॉग' को डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन का रचनात्मक साथ मिला। इसी साल अप्रैल की एक शाम विशेष गरिमा में ढल गई, जिसने राजधानी के कला जगत को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि संवाद और संवेदना की नई जमीन भी तैयार की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से आयोजन को विशिष्ट आयाम दिया। उन्होंने डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन की ओर से पंजाबी साहित्य की मशहूर लेखिका पद्मश्री अजीत कौर और समकालीन चित्रकला की सशक्त हस्ताक्षर अर्पणा कौर को सम्मानित किया। डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन के महासचिव नीरज जैन ने इस मंच को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा दी है। सृजन व सेवा के माध्यम से साहित्यकारों के जीवन व समाज कल्याण में जुटे नीरज जैन के प्रयास निस्संदेह अनुकरणीय हैं। वे अपनी रचनाओं में समय की सूक्ष्म अनुभूतियों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

सामयिक

अजमत

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

इस्तीफा नहीं, यह युवाओं के धैर्य की जीत है

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ सिंहासन जनता से बड़ा नहीं होता। सत्ता चाहे जितनी शक्तिशाली हो जाए, यदि जनता संविधान पर भरोसा रखते हुए अहिंसा के रास्ते पर डटी रहे, तो अंतत: उसे सुनना ही पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा यदि आज देश की राजनीति की सबसे बड़ी ख़बर है, तो इसलिए नहीं कि एक मंत्री ने पद छोड़ा है, बल्कि इसलिए कि यह लाखों युवाओं के धैर्य, संयम और लोकतांत्रिक विश्वास की कहानी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

यह कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई थी।

15 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय में हुई एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी ने देशभर में तीखी बहस छेड़ दी। लाखों युवाओं ने इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह महसूस किया। बाद में स्पष्टीकरण आया कि टिप्पणी का आशय अलग थाऔर उसे गलत समझा गया, लेकिन तब तक देश के युवाओं के भीतर जमा आक्रोश शब्दों से आगे बढ़ चुका था। उसी दौर में काकरोज़ जनता पार्टी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बनकर उभरा—उस पीढ़ी का प्रतीक, जिसने तय कर लिया कि अपमान का जवाब हिंसा से नहीं, लोकतांत्रिक प्रतिरोध से दिया जाएगा।

फिर दिल्ली का जंतर-मंतर देश की धड़कन बन गया। जो वहाँ पहुँचा, वह केवल धरने में शामिल नहीं हुआ, उसने भारत को उसके सबसे सुंदर रूप में देखा। तपती धूप थी। किसी का पसीना बह रहा था तो दूसरा अपना गमछा बढ़ा देता था। कोई पसीने से न भीगे तो अनजान लोग उसेहवा करने लगते। किसी के पास पानी था तो वह अपना नहीं, सबका था। किसी के टिफ़िन में चार रोटियाँ थीं, तो वह छह लोगों में बाँटी जा रही थीं। कोई रातभर जागकर सुरक्षा देख रहा था, कोई क्रांति के गीत गा रहा था, कोई संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था। वहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था, कोई धर्म नहीं पूछ रहा था। पूछा जा रहा था-'भाई, खाना खाया?' 'आओ यहाँ बैठ जाओ ?' 'दवा चाहिए?' शायद लोकतंत्र का सबसे सुंदर चेहत भी थी। पुलिस की बैरिकेडिंग थी। लाठियाँ भी थीं। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ थी-एक-दूसरे पर भरोसा।

उनके मन में गुस्सा था, लेकिन हाथों में पत्थर नहीं थे। पीड़ा थी, लेकिन आगज़नी नहीं थी। लाठियाँ थीं, लेकिन जवाब में हिंसा नहीं थी। वे संविधान लेकर बैठे थे। वे बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। वे गांधी का रास्ता याद कर रहे थे। उनके हाथों में पोस्टर थे-'निकम्मी सरकार को बदलना है', 'शिक्षा का ऐसा हाल ख़त्म करना है', 'कलम से दूर क्यों कुदाल?' यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति थी।

धीरे-धीरे यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, मुंबई सहित देश के लगभग हर हिस्से में युवा एकत्र होने लगे। शायद ही कोई राज्य बचा हो जहाँ से युवाओं ने समर्थन न भेजा हो। विश्वविद्यालयों में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़ते गए। गांधीवादी संगठन, नागरिक अधिकार समूह, छात्रसंगठन और लोकतांत्रिक मंच खुलकर समर्थन में आए। सीजेपी सहित अनेक सामाजिक समूहों और स्वयंसेवकों ने कानूनीसहायता, राहत, चिकित्सा और संगठनात्मक सहयोग दिया। यह किसी एक दल का आंदोलन नहीं रहा; यह उस पीढ़ी का आंदोलन रहा, जो अपने भविष्य को बचाना चाहती थी।राजनीति ने पहले इसे अनदेखा करने की कोशिश की। फिर इसे छोटा बताने की कोशिश हुई। फिर इसे बदनाम करने की कोशिश हुई। लेकिन जब लाखों युवाओं कीआवाज़ पूरे देश में गूँजने लगी, तब चुप्पी टूटने लगी।

इसी बीच देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया। उसके बाद भी देशभर में बहस जारी रही। दूसरी ओर जंतर-मंतर से लोग लगातार संवाद, सत्याग्रह और संवैधानिकसमाधान की बात करते रहे। यह केवल सरकार और आंदोलन के बीच की लड़ाई नहीं थी; यह दो रास्तों की लड़ाई थी-एक रास्ता सत्ता के अहंकार का और दूसरा जनता के धैर्य का।

आखिरकार जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया, तो लाखों युवाओं ने इसे अपनी जीत नहीं, लोकतंत्र की जीत कहा। क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति की हार का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने उस विश्वास का सम्मान किया कि लोकतंत्र में जनता की शांतिपूर्ण आवाज़ अंतत: सत्ता तक पहुँचती है।

इस आंदोलन का सबसे बड़ा नायक कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं, कोई दल नहीं था। सबसे बड़ा नायक वह छात्रथा, जिसने किराया उधार लेकर दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। वह युवती थी, जिसने घरवालों की चिंता के बावजूद जंतर-मंतर पहुँचने का साहस किया। वह साथी था, जिसने लाठी खाने के बाद भी अपने साथी को पानी पिलाया। वह डॉक्टर था, जिसने बिना शुल्क उपचार किया। वह अधिवक्ता था, जिसने गिरफ्तार युवाओं के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। वह माँ थी, जिसने बेटे से कहा-'डटे रहो, लेकिन संविधान का रास्ता मत छोड़ना।'

लोकतंत्र संसद से चलता है, लेकिन उसकी आत्मा जनता में बसती है। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल अदालतों की किताब नहीं, जनता का जीवित दस्तावेज़ है। गांधी केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि संघर्ष की आज भी सबसे प्रभावी भाषा हैं। और युवा केवलभविष्य नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इतिहास में किस रूप में दर्ज होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जंतर-मंतर की धूप, उन युवाओं का पसीना, अनजान लोगों काएक-दूसरे को पंखा झलना, लाठी खाने के बाद भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ना और सत्याग्रह पर अडिग रहना-ये दृश्यभारतीय लोकतंत्र की स्मृति में बहुत लंबे समय तक दर्ज रहेंगे। लोकतंत्र की जीत कभी अचानक नहीं होती। वह धीरे-धीरे बनती है-एक कदम से, एक आवाज़ से, एक सत्याग्रह से और एक भरोसे से।

इस बार भी वही हुआ।

जीत किसी व्यक्ति की नहीं हुई।

जीत लोकतंत्र की हुई।

बरसात के मौसम में लीक से अलीक तक

व्यंग्य

सुरेश उपाध्याय
लेखक स्तंभकार हैं।

परीक्षाओं के दौर में आईएमपी का चलन ट्यूशन टीचर व गाइडों से शुरु हुआ जो कोचिंग क्लासों में आकर और विस्तार पा गया है। परीक्षाओ के दौर में पान व चाय की दुकान पर आईएमपी की उपलब्धता के समाचार भी आते रहे हैं। शैक्षणिक युग का यह अनुभव नौकरी व कॅरियर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं तक विस्तार पाता गया है। कोचिंग सेंटरो से लेकर एवजी परिक्षार्थियो तक आधुनिक तकनीक से पेपर लीक होकर अल्प समय में बडे भूभाग तक आसानी से पहुंचने लगे हैं। 'पकड़ा जाए वो चोर' की तर्ज पर जब पेपर लीक की जानकारी और होहल्ला होता तो फिर से परीक्षा हो जाती है। पहले से ही कार्यभार से प्रभावित न्यायालयों के लिए यह एक ओर क्षेत्र बढ़ जाता है। छात्रों व अभिभावकों की परेशानियों, चिंताओं, अवसाद और आत्म हत्याओं की घटनाओं से जो आवेग, आवेश व आक्रोश बना वह 'लीक' नहीं हो पाया और एक वृहद आंदोलन देशभर में खड़ा हो गया है। अनेको ने इसमें योगदान दिया तो बहुतेरों को इसमें अवसर मिला और अपने-अपने तरीके से उन्होंने अवसर का लाभ लिया है या भविष्य में लाभ के रास्ते तैयार किए हैं। देशव्यापी इस उद्वेलन से पेपर लीक के विरुद्ध फुलप्रुफ प्रणाली बनेगी तथा दोषियों को उचित दंड मिलेगा, ऐसा विश्वास है।

बरसात के आते ही च्पानी चू रहा हैज्ज एक आम शिकायत रहती थी। टपक-टपक बरसने से तेज बौछार तक 'पानी का चू ना' लगा रहता था। कच्चे घरों में लगे लोहे के पतरो (टीन शेड) व कवेलू की छतों में यह आम बात थी। खास बात थी, इससे बचाव की और तरीका चू रहे पानी को बाल्टियों में समेटना। घर के बाल्टी, डिब्बे व बर्तन तक इसमें लगाना पड़ सकते थे। इनके पूरे भरने पर पानी बाहर फेंककर फिर से उसी जगह पर रखने की जिम्मेदारी अलग होती थी। मकान पक्का बना तो गर्डर पत्थर की छत से पानी रिसने लगा, छत के ऊपर बरसाती और टीन शेड का चलन आया। सीमेंट-कांक्रीट की छत के युग में पानी का लीकेज शुरु हुआ और शुक्र है वाटर प्फिंग भी चलन में आ गया है। चू ने से लीक की इस यात्रा में चू ना (शब्द) तो विलुप्त हो गया और लीक सर्वव्यापी हो गया है। कुएं, बावड़ी तो रहे नहीं और न उनके लिए चिंताए रही हैं।

अलबत्ता बांध, नहरें, तालाब आदि के लीक होने के समाचार गाहे बगाहे आने लगे हैं। इनके निर्माण ने तो व्यवसाय व रोजगार के अवसर दिए ही थे, लीक होने की घटनाओं/ दुर्घटनाओं ने इन आपदाओं में नए-नए अवसर दिए और शीघ्रातीशीघ्र दिए हैं।

लीक (बनी बनाई लकीर) पर चलना अर्थात् मान्य परम्पराओं पर चलना एक गुण माना जाता रहा है और रुढ परम्पराओं को चुनौती देने वाले 'अलीक' लिखते या कहलाते रहे हैं। मीटिंगों, बैठकों की चर्चाए, निर्णय जिन्हें गोपनीय रहना था या जिनकी सार्वजनिक घोषणा के लिए उचित अवसर की जरुरत रहती थी, वे भी धीरे से प्रचारित/प्रसारित होने लगी और सूत्रों के हवाले से छपने व विस्तारित होने लगी है। यह प्रक्रिया भी 'लीक' की संज्ञा से नवाजी जाने लगी तथा संदेही की खोज व उसको दंडित करने का आधार बनने लगी। लीक की प्रक्रिया में जासूसी का भी प्रयोग किया गया तथा इसका उपयोग बदले भुनाने व निपटाने के लिए भी हुआ ही होगा, ऐसा माना जाता है।

परीक्षाओं के दौर में आईएमपी का चलन ट्यूशन टीचर व गाइडों से शुरु हुआ जो कोचिंग क्लासों में आकर और विस्तार पा गया है। परीक्षाओ के दौर में पान व चाय की दुकान पर आईएमपी की उपलब्धता के समाचार भी आते रहे हैं। शैक्षणिक युग का यह अनुभव नौकरी व कॅरियर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं तक विस्तार पाता गया है। कोचिंग सेंटरो से लेकर एवजी परिक्षार्थियो तक आधुनिक तकनीक से पेपर लीक होकर अल्प समय में बडे भूभाग तक आसानी से पहुंचने लगे हैं। 'पकड़ा जाए वो चोर' की तर्ज पर जब पेपर लीक की जानकारी और होहल्ला होता तो फिर से परीक्षा हो जाती है। पहले से ही कार्यभार से प्रभावित न्यायालयों के लिए यह एक ओर क्षेत्र बढ़ जाता है। छात्रों व अभिभावकों की परेशानियों, चिंताओं, अवसाद और आत्म हत्याओं की घटनाओं से जो आवेग, आवेश व आक्रोश बना वह 'लीक' नहीं हो पाया और एक वृहद आंदोलन देशभर में खड़ा हो गया है। अनेको ने इसमें योगदान दिया तो बहुतेरों को इसमें अवसर मिला और अपने-अपने तरीके से उन्होंने अवसर का लाभ लिया है या भविष्य में लाभ के रास्ते तैयार किए हैं।

देशव्यापी इस उद्वेलन से पेपर लीक के विरुद्ध फुलप्रुफ प्रणाली बनेगी तथा दोषियों को उचित दंड मिलेगा, ऐसा विश्वास है। हनी ट्रेप से लेकर आर्थिक लाभ के लालच में सुरक्षा प्रणाली से जुड़े लीक के समाचार भी आते रहे हैं। लीक (रिसन) के कई क्षेत्र और भी हैं तथा वे देश के अर्थतंत्र को खोखला कर रहे हैं, उस लीक (रिसन) को रोकने के लिए भी ठोस व प्रभावी प्रणाली बने, यह छोटी सी आकांक्षा है, आपकी क्या राय है?

हमारा यही संदेश नशा मुक्त हो प्रदेश, सेमरीहरचंद में मानव श्रृंखला बनाकर दिया संदेश

सोहागपुर। प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत समीपवर्ती ग्राम सेमरीहरचंद में मानव श्रृंखला बनाकर एवं नशामुक्ति की निकली जनजागरूकता रैली। नशामुक्ति जन-जागृति अभियान के तहत शासकीय कन्या उमा विद्यालय एवं शासकीय बालक उमा विद्यालय सेमरहरचंद में खेल, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। इस, अवसर पर सेमरीहरचंद चौकी प्रभारी एसआई विवेक यादव ने कहा कि किसी प्रकार का नशा परिवार के स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के साथ आर्थिक स्थिति का क्षरण होकर घर परिवार की खुशियों नशा ली लेता है। आपने आगे कहा छात्र छात्राओं से आव्हान किया कि यदि घर, परिवार या आसपास का कोई व्यक्ति नशे की लत का शिकार है तो उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी क्रम में शासकीय बालक उमा विद्यालय के विद्यार्थियों से सामूहिक शपथ लेकर विद्यालय परिसर से पीपल चौक तक जागरूकता रैली निकाली। रैली में छात्र छात्राओं ने नशे के विरोध में नारेबाजी करते समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षक, शिक्षिकाओं के अलावा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इधर नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी एवं एएसआई गणेश राय ने बताया कि नशे से दूरी है जरूरी,गुड टच बेड टच एवं सायबर क्राइम से संबंधित कार्यक्रम विवेकानंद स्कूल सोहागपुर में सोमवार 11:30 बजे से आयोजित किया गया है।

सोहागपुर में ब्लाक बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, बदलेगी तस्वीर युवाओं को मिलेगा रोजगार : क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह

सोहागपुर

सोहागपुर ब्लाक बनेगा औद्योगिक क्षेत्र बदलेगी यहां की तस्वीर बदलने से यहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र को व्यापार की नई रफ्तार मिलेगी। सोहागपुर नगर एवं क्षेत्र के विकास को नई गति देने की दिशा में सोहागपुर विधानसभा को एक के बाद एक महत्वपूर्ण सौगातें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद क्षेत्र के मातापुरा वार्ड में रू. 9,15,048 की लागत से सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही व्यायामशाला निर्माण के लिए रू. 5 लाख तथा प्रजापति समाज के सामुदायिक भवन के लिए रू. 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। भवन का निर्माण भूमि उपलब्ध होने के बाद कराया जाएगा। उक्त उद्गार क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने मातापुरा में भूमिका पूजन एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण के अवसर पर कहें। इस अवसर पर इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, वरिष्ठ वकील जेपी माहेश्वरी, प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी गौरव अग्रवाल,उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी कुमार सरोज, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल गहरैया, अभिषेक चौहान, पार्षद गौरव पालीवाल, पार्षद आशीष विश्वकर्मा, पार्षद भास्कर , इंद्र कुमार दीवान, , भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, एल्डरमैन राकेश मंडल, वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर मालवीय, मंडल महामंत्री मिथिलेश ठाकुर, एल्डरमैन नितिन कहार नगर पंचायत परिषद नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा,

संजय परसाई, प्रशांत मालवीय, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। क्षेत्रीय विधायक ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार सोहागपुर विधानसभा के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। स सोहागपुर क्षेत्र में औधोगिक आपने कहा सोहागपुर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन संभावित स्थानों का चयन कर निरीक्षण किया गया है। सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है। यदि योजना सफल होती है तो किसानों की भूमि का अधिग्रहण उनकी वर्तमान बाजार कीमत से चार गुना अधिक मुआवजे मिल सकेगा। इस भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

मोहासा ओघोगिक क्षेत्र में करीबन 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आने वाले एक वर्ष में इस क्षेत्र के विस्तार के साथ एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अपने विस्तृत उद्बोधन में आपने आगे कहा कि विद्युत व्यवस्था मे जनता की समस्या को समझते हुए 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। इससे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति काफी हद तक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। नगर पंचायत परिषद ने डेढ़ करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। ग़लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर मिलेगा विशेष उपहार क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को नियमित राशि के अतिरिक्त रू. 250 की अतिरिक्त राशि उपहार स्वरूप प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भविष्य में योजना की राशि को रू. 3,000 से बढ़ाकर रू 5,000 प्रतिमाह करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है। आपने अंत में कहा कि 29 जुलाई को मुख्यमंत्री करेंगे मुहासा औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेंगे।इस दौरान कार्यक्रम में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर औद्योगिक परियोजनाओं को शीघ्र गति देने एवं नए उद्योगों की स्थापना पर विशेष चर्चा की जाएंगी। ताकि सोहागपुर विधानसभा के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हों। माता पुरा में क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह का फलों से तुला दान किया गया।इसी समय क्षेत्रीय सांसद भी कार्यक्रम में पहुंचे। आयोजकों ने क्षेत्रीय सांसद दर्शनसिंह का भी फलों से तुला दान किया गया।

हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी

सूंड से उठाकर पटकने के बाद पैर से कुचला, ऑटो चालक की मौत

इंदौर(नप्र)। एमपी के इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में हाथी के हमले से एक ऑटो चालक की जान चली गई। घटना का वीडियो रविवार को सामने आया जिसमें हाथी एक व्यक्ति को सूंड से उठाकर जमीन पर पटकता और फिर उसे पैर से कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। घायल चालक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में महावत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार शाम करीब 4ः18 बजे राजनगर पुलिस चौकी के पास हुई। मृतक की पहचान 49 वर्षीय विजय उर्फ लक्ष्मण राव होलकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हाथी को रोककर उसे गुड़ खिलाना शुरू किया।

उज्जैन से इंदौर लाया गया था हाथी – चंदन नगर थाना पुलिस के अनुसार हाथी को उज्जैन से जैन समाज के एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर लाया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद महावत हाथी को लेकर इलाके में घूम रहा था और भिक्षावृत्ति कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

बड़ी मुश्किल से हाथी को मौके से हटा सके – घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह हाथी को वहां से हटाया और घायल विजय को पहले जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें वर्मा यूनियन अस्पताल रेफर किया गया, जहां शाम करीब 7:30 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विजय अपने पीछे पत्नी, एक बेटे और अन्य परिजनों को छोड़ गए हैं।

महावत हिरासत में, इंदौर चिड़ियाघर को सूचना भेजी – थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महावत को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही हाथी के संबंध में इंदौर चिड़ियाघर के अधिकारियों को भी सूचना भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी में घटना के समय मृतक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद समारोह में दी कारगिल वीरों को श्रद्धांजलि

सैनिकों के त्याग और बलिदान से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं : उप मुख्यमंत्री

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सम्मेलन में कारगिल के वीर शहीदों को श्रंद्धाजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक वीरता और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। सैनिकों के त्याग और बलिदान से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कारगिल युद्ध में वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजीलगाकर कठिनतम परिस्थितियों में देश को विजय दिलाई। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने सेना की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाये। भारत तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। देश की आजादी के समय वीरों ने जो सपने देखे थे उन्हें 2047 तक पूरा करके देश को विश्वगुरू बनायेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने हाल ही में समान नागरिक सहिंता कानून पास करके सबकों समान अधिकार दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश एक विधान एक निशान और एक प्रधान का सपना पूरा किया। हमारे सैनिकों ने कश्मीर से आतकवाद की जड़े उखाड़ फेकी विन्ध्यशधरा में पूर्व सैनिकों का स्वागत करते हुए हम सबकों बड़ी प्रसन्नता हो रही है। विन्ध्य ने दुनिया को साफेद बाघ दिया है इसके साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना का नेतृत्व करने वाले थल सेना अध्यक्ष जनरल

उपेन्द्र द्विवेदी तथा नौसेना अध्यक्ष एडमिनरल दिनेश त्रिपाठी विन्ध्न के ही लाल हैं। सेवानिवृत्त के बाद भी सभी पूर्व सैनिक देश के विकास में अच्छा योगदान दे रहे हैं। समारोह में श्री प्रदीप जोशी ने कहा कि पोखरन दो की घटना ने हमारे देश की मानसिकता और युद्ध नीति को बदल दिया। कारगिल युद्ध की सफलता ने इस नई रणनीति को सफल सिद्ध किया। समारोह में पूर्व विधायक तथा सेवानिवृत्त सैनिक श्री लक्ष्मण सिंह तिवारी ने कहा कि विन्ं क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन हैं। रीवा में सैनिक स्मारक बनाया जाय। समारोह में जनपद अध्यक्ष श्री लालबहादुर सिंह तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। समारोह में नगर निगम के अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल बी.के. चतुर्वेदी, विग्रेडियर डीएस त्रिपाठी, मेजर जनरल बीएस शर्मा तथा बड़ी संख्या में विन्ध्य क्षेत्र महाकौशल और छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। समारोह का संचालन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री रमेश पाण्डेय ने किया।

कान्हा टाइगर रिजर्व से दुखद खबर

ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुए की इलाज के दौरान मौत, रेस्क्यू के वक्त शरीर पर मिले थे चोट के निशान

जबलपुर (नप्र)। कान्हा टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। रिजर्व के बफर क्षेत्र में आने वाले सिझोरा परिक्षेत्र के ग्राम खटोला में एक ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है। रेस्क्यू के बाद उसे मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकीय निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जब तेंदुआ ग्रामीण के घर में घुसा था, तब रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे ट्रेंकुलाइज किया और सुरक्षित रेस्क्यू किया था। हालांकि, पकड़ने के दौरान ही तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे, जिसके बाद उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देकर मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय भेज दिया गया था।

डॉक्टरों की कोशिशें रहीं नाकाम, शनिवार को तोड़ा दम – मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम लगातार तेंदुए की सेहत पर नजर बनाए हुए थी और उसका इलाज कर रही थी, लेकिन गंभीर चोटों के चलते शनिवार को उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तय की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पुष्टि की कि तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। मौत का प्राथमिक कारण शरीर पर आई पुरानी या रेस्क्यू के वक्त की चोटें माना जा रहा है।

वन्यजीवों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल – कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार वन्यजीवों की मौत होने से चिंता बढ़ गई है। इस क्षेत्र में बाघों और अन्य वन्यजीवों की मौतों के मामलों को लेकर पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है, जिसके बाद से प्रशासन पर मौतों के आंकड़ों को रोकने का भारी दबाव बना हुआ है।

भोपाल में बदमाशों ने दो कार सहित चार वाहन फोड़े

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र इलाके में शनिवार-रविवार देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कॉलोनी में खड़े वाहनों को निशाना बनाते हुए उनके कांच पत्थरों से फोड़ दिए।पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, देर रात दो युवक बाइक पर सवार होकर कॉलोनी में पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे और घरों के बाहर खड़े चार पहिया वाहनों को निशाना बनाया। बदमाशों ने पत्थरों से एक-एक कर वाहनों के शीशे तोड़ दिए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सुबह जब वाहन मालिक घरों से बाहर निकले तो वाहनों के टूटे हुए कांच देखकर उनके होश उड़ गए। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरू की जांच – घटना की सूचना मिलते ही कटारा हिल्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले, जिसमें दो बाइक सवार संदिग्ध वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

गैंगरेप का 50 हजारी आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

सतना (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 22 जुलाई को देवांगना घाटी में छात्रा से हुए सनसनीखेज सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला को शनिवार शाम एसओजी और बहिलपुरवा पुलिस की संयुक्त टीम ने भरकूप थाना क्षेत्र के मड़था जंगलों में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी के हाथ में भी गोली लगी है। दोनों को शिवरामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

10 राउंड की क्रॉस फायरिंग, दो अवैध तमंचे बरामद – चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे मड़था के जंगलों में आरोपी की घेराबंदी की गई थी। खुद को घिरा देख 50 हजार के इनामी आरोपी जितेंद्र ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी, जिससे एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 राउंड फायर किए। पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह बाइक समेत गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोचकर उसके पास से दो अवैध तमंचे जब्त किए हैं।

जंगल में बॉयफ्रेंड को बंधक बनाकर की थी दरिंदगी – यह खौफनाक घटना 22 जुलाई को घटी थी। सतना की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा अपने 17 वर्षीय बॉयफ्रेंड के साथ देवांगना घाटी में बैठी थी।

■ राज्य मंत्री श्री पंवार सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने कुंवर चैनसिंह और उनके साथियों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन

अमर शहीद कुंवर चैनसिंह के शहादत दिवस पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

सीहोर (निप्र)। अमर शहीद कुँवर चैन सिंह के शहादत दिवस पर शासन की ओर से गाड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने अमर शहीद कुँवर चैनसिंह को श्रद्धा सुमन आर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अमर शहीद कुँवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो देश में लिए जिए उसी का जीवन सार्थक होता है। आज हम सभी ऐसे ही अमर शहीद वीर कुंवर चैनसिंह और उनके साथियों हिम्मत खां एवं बहादुर खां को श्रद्धांजली दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र में जागरण और चेतना की लहर के लिए स्वयं किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है। कुंवर चैन सिंह भी उन्हीं वीर शहीदों में से एक थे। कुंवर चैनसिंह को अंगेजों की ताकत का पता होते हुए भी वे अंगेजों से भिड़ गए, क्योंकि उनका हौंसला बुलंद था। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जो देश अपने क्रांतिकारियों के बालिदानों को याद नही करता है उसकी नींव हमेशा कमजोर होती है। एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र की बुनियाद में अनेक शहीदों के बलिदान छुपे होते हैं। हमारी वर्तमान और आने वाली सभी पीढ़ियों को अपने अमर शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता में ही राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति निहित है। हमारे देश ने सेकड़ों सालों तक गुलामी का बोझ झेला है। यदि उस समय हमारे देश के लोगों में एकता का भाव होता, तो शायद हमे इतने वर्षों तक गुलाम न रहना पड़ता। हमारे देश में भाईचारे की भावना सदियों पहले से रही, पर कुछ विदेशी आक्रांताओं ने आकर इस भाईचारे की भावना हो कमजोर किया और हम पर सैंकड़ों वर्षों तक राज किया। कार्यक्रम में विधायक श्री सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, अमर शहीद कुँवर चैन सिंह के वंशज एवं पूर्व विधायक श्री राजवर्धन सिंह, हिम्मत खां बहादुर खां के वंशज श्री जेडएके लोधी, भारत जोड़ो समिति के श्री बलवीर सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राजीव गुजराती, श्री अनूप सिंह, कलेक्टर श्री बालागुरु के., एसपी श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना, श्री राजकुमार गुप्ता, श्री सुदीप प्रजापति सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यशैली ही सुशासन की पहचान है

● राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है - संभागायुक्त

● भोपाल संभागायुक्त ने की राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा

सीहोर (निप्र)। भोपाल संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने सीहोर जिला पंचायत सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा तथा अविवादित नामांतरण के सभी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण किसी स्थिति में समय-सीमा से बाहर नहीं जाने चाहिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले में संचालित राजस्व संबंधी कार्यों के बारे में संभागायुक्त को जानकारी दी। संभाग आयुक्त ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से गांवों को राजस्व विवादों से मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा ग्राम स्तर पर आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान के प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी तथा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रशासन की रीढ़ हैं और प्रत्येक राजस्व प्रकरण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें। संभाग आयुक्त ने सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करने तथा आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में यह रहे उपस्थित

उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से सतत संपर्क बनाए रखने तथा किसानों से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यशैली ही सुशासन की पहचान है तथा इससे आमजन को त्वरित न्याय और बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर श्री रविंद्र परमार, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

अनुसूचित जाति सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास में जन्मदिवस पर तिथि भोज का आयोजन

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में संचालित शासकीय छात्रावासों में विशेष तिथियों तथा अवसरों पर जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, अधिकारियों तथा नागरिकों के सहयोग से विशेष भोज आयोजित किए जाने निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को अनुसूचित जाति सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास में सहकारिता विभाग की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अंजली धुर्वे द्वारा बालकों के लिए तिथि भोज का आयोजन किया गया। जिसमें डिप्टी कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बालकों के साथ बैठकर भोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन के विशेष अवसरों को छात्रावासों में रह रहे बालक-बालिकों के साथ मनाने से उन्हें पारिवारिक और स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है तथा उनमें सामुदायिक भावना का भी विकास होता है।

नलजल योजनाओं के कार्यो को गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गुरूवार को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी द्वारा जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल और समूह नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की विस्तृत समीक्षा करते हुए संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं प्रगतिरत योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विकासखण्डवार प्रगतिरत और पूर्ण हो चुकी नलजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों को घर पर ही नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को पूर्ण हो चुकी नलजल योजनाओं को शीघ्र हैंडओवर करने और हैंडओवर कार्यों को प्रमाणित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यो की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। अधिकारी नियमित रूप से कार्यो की मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर बनी जल समितियों को सशक्त बनाकर योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि एकल नलजल योजना अंतर्गत स्वीकृत 755 योजनाओं में से 642 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 113 योजनाओं में कार्य प्रगतिरत है। इनमें 50 नलजल योजनाओं में 76-99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा 42 नलजल योजनाओं में 51-75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार 11 नलजल योजनाओं में 26-50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। बैठक में गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना, हलाली समूह जल प्रदाय योजना, उदयपुरा समूह जल प्रदाय योजना के कार्यो के प्रत्येक चरण की जानकारी लेते हुए कार्य को गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन डॉ .घोरे ने अस्पताल के वार्डों का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे ने 24 जुलाई को मेटरनिटी वार्ड एवं ओपीडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएनसी वार्ड में मरीजों से वन टू वन चर्चा की। इस दौरान मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं के बदले , स्टॉफ द्वारा किसी प्रकार की राशि तो नहीं ली जा रही की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों एवं परिजनों को बताया कि अस्पताल में आपरेशन, दवाइयां, जननी एम्बुलेंस से आना-जाना, समस्त सेवाएं निःशुल्क दी जाती है। आर्थिक लाभ के लिए कोई भी अस्पताल का स्टॉफ राशि की मांग करता है तो उनकी शिकायत करें। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लगे डिस्प्ले नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रभारी सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.घोरे ने सोनोग्राफी कक्ष के निरीक्षण के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। एएनसी कक्ष में निरीक्षण के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा राऊंड प्रारंभ नहीं करने पर स्पष्टीकरण लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ओटी का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

■ नव्या योजना की बालिकाओं ने अंतरजिला किया शैक्षणिक भ्रमण

औद्योगिक कार्यप्रणाली और रोजगार के अवसरों से हुई रूबरू

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल, 40 बालिकाओं ने आधुनिक वस्त्र उद्योग को करीब से जाना

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नव्या योजना के अंतर्गत जिले की 40 बालिकाओं का शैक्षणिक एवं औद्योगिक भ्रमण रायसेन जिले की बुधनी स्थित वर्धमान फैब्रिक्स में आयोजित किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य बालिकाओं को औद्योगिक वातावरण से परिचित कराना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें कौशल विकास एवं रोजगार के विविध अवसरों की जानकारी प्रदान करना था। भ्रमण के दौरान बालिकाओं ने वर्धमान फैब्रिक्स की आधुनिक उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए धागे से कपड़ा तैयार होने तक की संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने अत्याधुनिक मशीनों के संचालन, गुणवत्ता परीक्षण, प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाओं को समझा। उद्योग के अधिकारियों ने वस्त्र निर्माण क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार, प्रशिक्षण एवं करियर की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए बालिकाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। आईटीआई की प्राचार्या सुश्री कविता रघुवंशी साथ मौजूद रही उन्होंने बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए तकनीकी दक्षता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बालिकाओं से आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री संतोष रघुवंशी ने शैक्षणिक एवं औद्योगिक भ्रमण बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास, करियर मार्गदर्शन तथा व्यावहारिक ज्ञान को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि नव्या योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी अवसरों से जोड़कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की जानकारी साझा की है। भ्रमण के उपरांत बालिकाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आधुनिक उद्योग की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखने और विशेषज्ञों से संवाद करने का अवसर उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा।

व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर 05 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश चंदेल और खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कुबेरेश्वर धाम स्थित होटल, भोजनालय सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 05 दुकानों से 05 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में विद्यार्थियों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के उद्देश्य से एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय विदिशा से मनोचिकित्सक डॉ अशोक राजपूत, नैदानिक मनोवैज्ञानिक श्री रवि सिंह सेंगर एवं मनोचिकित्सा नर्सिंग अधिकारी श्री गिरिराज सैनी ने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को तनाव प्रबंधन, करियर के दबाव से निपटने और खुलकर अपनी बात रखने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही छात्राओं को जिला चिकित्सालय में संचालित 'मन क्लीनिक और टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 'मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना या मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत पहचानना है।

मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

रायसेन (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी अनुसार कंपकंपी के साथ तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी होना, बेचैनी, कमजोरी, सुस्ती, मितली, ठंड, तपन महसूस होना आदि मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। इसे बचाव के उपाय आवश्य करें और नजदीकी चिकित्सालय में जाकर डॉक्टर से परामर्श तथा उपचार लें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें और खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगायें। हल्के रंग के कपड़े पहनें एंव हाथ पैरों को पूरा ढ़कें। हर सप्ताह कूलर, टंकी और बैरल के पानी को बदलें। आस पास पानी को जमा न होने दें। इसके साथ ही तेज बुखार, उल्टी तथा शरीर में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डेंगू फैलाने वाला मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है। कूलर, टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रीज की ट्रे, फूलदान, नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायर इत्यादि में को ढक कर रखें तथा अधिक दिनों तक यहां पानी जमा न रहने दें।

संभाग आयुक्त बनोठ ने संभाग में निर्माण कार्यों और स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की

● सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखा जावे

● विभागों में अंतर समन्वय कर कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें : संभागायुक्त बनोठ

नर्मदापुरम (निप्र)। संभाग आयुक्त श्री श्रीकांत बनोठ की अध्यक्षता में संभागीय कार्यालय के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन एवं स्वीकृत कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीईयू, सेतु निर्माण, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्रामीण यांत्रिक सेवा, एनएचएआई, जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान संभागायुक्त श्री बनोठ ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निविदा (टेंडर) में निर्धारित पूर्णता तिथि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूर्ण किया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर प्रगति की सतत समीक्षा की जाए, ताकि किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। बैठक में सिंचाई संबंधी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त श्री बनोठ ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा समय पर उपलब्ध कराया जाए।

इसके लिए शासन के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण तैयार कर संबंधित जिला कलेक्टरों को शीघ्र प्रेषित किए जाएं, ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में विलंब न हो। संभागायुक्त श्री बनोठ ने कहा कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए विकास परियोजनाओं को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण करें, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के लिए युवा समन्वयकों की बैठक संपन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले के सभी सात ग्रामीण युवा समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री विकास खराडकर ने की। बैठक में श्री खराडकर ने बताया कि कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंडों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत रैली, नशामुक्ति शपथ, खेल गतिविधियाँ, संगोष्ठी सहित विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में श्री महेन्द्र पचलानिया (नर्मदापुरम), श्रीमती चंदा मिश्रा (सोहागपुर), श्री नारायण बाबरिया (सिवनी मालवा), श्रीमती सुषमा अहिरवार (बाबई), श्री देवेन्द्र उरहा (बनखेड़ी), श्रीमती आरती शर्मा (केसला) एवं श्री प्रीतम सिंह पूर्विया (पिपरिया) उपस्थित रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। जिला खेल अधिकारी श्री विकास खराडकर ने समन्वयकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए।

जिला प्रबंधक, लोक सेवा श्री आनंद झेरवार ने किया इटारसी और केसला लोक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण

साफ-सफाई और ऑनलाइन प्रक्रिया पर दिए कड़े निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। सुशासन और पारदर्शी सेवा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन श्री आनंद झेरवार ने इटारसी और केसला स्थित लोक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। श्री झेरवार द्वारा लोक सेवा केंद्र इटारसी के निरीक्षण के दौरान केंद्र की समग्र व्यवस्था और लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई।

निरीक्षण में पाया गया कि कुछ आवेदनों के ऑनलाइन प्रिंट पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं थे। इस पर श्री झेरवार ने ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि सभी ऑनलाइन भरे गए आवेदनों में आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिए जाएं और शत प्रतिशत ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा केंद्र और शौचालय में साफ-सफाई और बेहतर रखने, सभी ऑपरेटरों के यूनिफॉर्म में समय पर उपस्थित रहने, उपस्थिति रजिस्टर को पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक को आवेदन की पावती देना अनिवार्य है और भरे गए सभी आवेदन अगले कार्य दिवस तक संबंधित कार्यालयों में भेजे जाएं। CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग का विधिवत संधारण कर मांग पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया। लोक सेवा केंद्र केसला में सेवावार संधारित रजिस्टरों और आवेदनों की जांच की गई। यहां भी आवेदन की हार्डकॉपी अगले दिन संबंधित कार्यालयों में भेजने, ऑनलाइन आवेदन और पावती का प्रिंट साफ-सुथरा निकलने के निर्देश दिए गए। श्री झेरवार ने दोनों केंद्रों में सभी सेवाओं की सूची और आवेदन शुल्क की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने, प्रत्येक आवेदक को पावती देने और ऑपरेटरों को आवेदकों से विनम्र एवं शालीन व्यवहार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी केंद्रों पर निर्धारित स्टाफ, पेयजल, बैठक व्यवस्था, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, फर्नीचर और प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध हो और उनका सुचारू संचालन हो।

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा मानसिक समस्याओं के लक्षणों की समय पर पहचान एवं उपचार के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में मनकक्ष नोडल अधिकारी डॉ. अर्शी सदफ, नर्सिंग ऑफिसर रेशमा कुरैशी एवं उमंग काउंसलर ममतेश राठौर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

समृद्ध किसान
समृद्ध प्रदेश
किसान
कल्याण वर्ष 2026
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
बलराम कृषि महोत्सव
27 जुलाई, 2026 | नई कृषि उपज मंडी, खण्डवा
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि
₹3300 करोड़+ का
82 लाख + किसानों को
अंतरण एवं संवाद
मुख्यमंत्री
डॉ. मोहन यादव
द्वारा
कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण
आधुनिक खेती का मंत्र
उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई
और डिजिटल कृषि सेवाओं की जानकारी
जैविक खेती से बढ़ेगी आय
प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण,
जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि पर विशेष फोकस
जानकारी का एक मंच
कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन,
सहकारिता सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी
विशेषज्ञों से सीधा संवाद
खेती की समस्याओं का समाधान, नई तकनीकों और
बाजार आधारित कृषि मॉडल की जानकारी
मौसम के अनुसार खेती की तैयारी
मृदा स्वास्थ्य, मौसम आधारित खेती और
जलवायु अनुकूल कृषि के टिप्स
D-11065/26
सीधा प्रसारण
Webcast.gov.in/mp/cmevents
@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP
JansamparkMP